RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 23 अंक 04 05 दिसम्बर 2022

जगत विज़न

एनसीआरबी की रिपोर्ट–शर्मसार हुआ प्रदेश

अपराधों का गढ़ बन गया मध्यप्रदेश

कटघरे में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की काबिलियत

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका **वर्ष 23 अंक 04 05 दिसम्बर 2022**

एनसीआरबी की रिपोर्ट–शर्मसार हुआ प्रदेश

अपराधों का गढ़ बन गया मध्यप्रदेश

कटघरे में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की काबिलियत

(पृष्ठ क्र.-6)

■ रंग ला रही पूर्व सीएम कमलनाथ की मेहनत 22
■ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों के अंत की शुरूआत 32
■ आदिवासियों पर मोदी, कोजरीवाल और कांग्रेस की नजर 34
■ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कांग्रेस मंजधार में 40
■ क्या केजरीवाल कामयाब हो सकते हैं? 42
■ मैनपुरी में अखिलेश यादव की दांव पर लगी साख 46
■ सौरभ गांगुली पर सब पार्टियों के नज़र 50
■ पीड़ितों हेतु कार्यरत संगठनों ने ब्रिटेन संसद में 54
■ क्या भारत में एक देश एक आरक्षण व्यवस्था जरूरी है? 56
■ पराली से प्रदूषण समस्या है तो समाधान भी है 58
■ वरदान बने बढ़ती आबादी 60
■ There is a fundamental error in the thinking of the 61

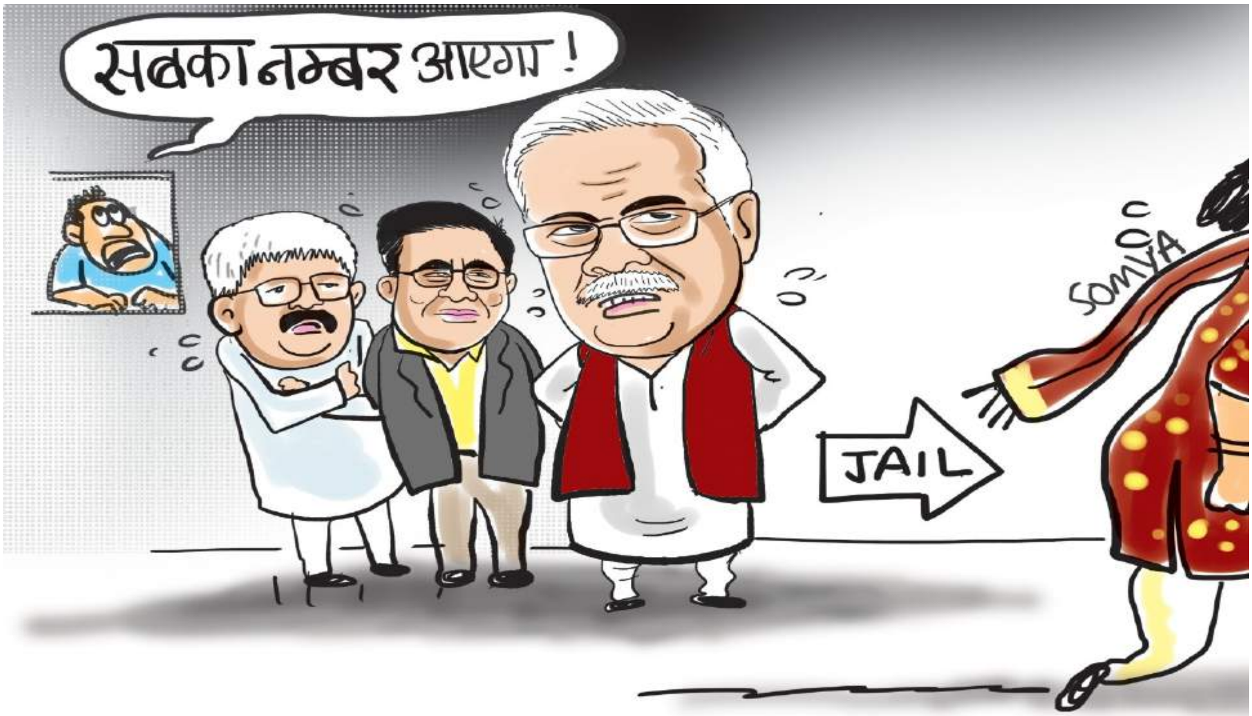
सबका नम्बर आएगा !
JAIL
SOMYA

जैसे करम करोगे वैसा फल देगा भगवान..
गीता जयंती

भारत जोड़ो यात्रा : देश की दिशा बदलने का प्रयास

राहुल गांधी की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी अब मध्यप्रदेश से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। इस कुल 03 हजार 570 किमी लंबी पैदल यात्रा में से राहुल गांधी और उनके सहयात्री 02 हजार किमी से ज्यादा भारत नाप चुके हैं। जिन 13 राज्यों से यह यात्रा गुजर रही है और गुजरेगी, उनमें से 09 राज्य पूरे हो चुके हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने देश के सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के मनमौजी बेटे से हटकर एक अलग रूप में जनता से संवाद करने की कोशिश की है और इस बात को उनके घोर-विरोधी भी मानने लगे हैं। यही देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की चिंता का सबब भी है। यहां असल सवाल यह है कि अब तक सुचारू रूप से सम्पन्न इस यात्रा से राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ, उन्होंने अपनी स्थापित छवि को बदलने में कितनी कामयाबी पाई और सबसे अहम सवाल कि उनकी पार्टी कांग्रेस के प्रति जनविश्वास किस हद तक लौटा है या लौटेगा? या फिर यह यात्रा भी महज राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगी? आगामी विधानसभा चुनाव और फिर आम चुनाव पर इस यात्रा का क्या असर हो सकता है, इसका आकलन पांच महीने बाद ही संभव हो पाएगा। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के आगाज़ पर उत्साह का जो माहौल है, उसे देखकर अंजाम की कल्पना की जा सकती है। बेशक, इन सवालों के जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं, जो एक परिपक्व राजनेता राहुल गांधी को तराशने के लिहाज से अहम हैं। राहुल गांधी का राजनीति में प्रवेश अपने पिता की तरह अकस्मात नहीं था, लेकिन बतौर सक्रिय राजनीतिज्ञ अपने 18 साल से राजनीतिक कॅरियर में राहुल ज्यादातर समय एक युवा, ईमानदार गंभीर राजनेता के रूप में ही जाने जाते रहे हैं। यह यात्रा उनके लिए केवल राजनैतिक ही नहीं व्यक्तिगत तौर पर भी काफी मायने रखती है। गांधी परिवार से कोई वैचारिक तौर पर सहमत हो या न हो, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस परिवार में पहले इंदिरा गांधी और उनके बाद राजीव गांधी की हत्याएं नफरती और विभाजनकारी राजनीति का ही परिणाम हैं। राहुल गांधी जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उन्होंने लगातार इस नफरत की मुखालफत की है।

निश्चित ही इस यात्रा के बाद कांग्रेस एक नये अवतार और नई आशा के साथ एक अरसे के बाद देश की सबसे पुरानी और अभी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे देश की राजनीति को नयी दिशा मिल सकती है। साथ ही जनाधार हासिल करने के संकट से इतिहास के सबसे कठिन दौर में गुजर रही कांग्रेस के लिए यह संजीवनी साबित हो सकता है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने का फैसला लेकर एक सराहनीय काम किया है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस जनाधार के लिहाज से कुछ और कमजोर हुई है, जबकि भाजपा की सत्ता का दायरा कुछ और बढ़ गया है। वहीं इन सालों में देश में सांप्रदायिकता और धर्मांधता के फसाद भी बढ़े हैं। लेकिन इस यात्रा ने इन पहलुओं को न छूते हुए देश को एक नया संदेश देने का प्रयास किया है। जिसमें देश में लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। यह यात्रा आने वाले चुनावों में कांग्रेस को नई दिशा और दशा प्रदान करेगी।

विजया पाठक

एनसीआरबी की रिपोर्ट–शर्मसार हुआ प्रदेश

अपराधों का गढ़ बन गया मध्यप्रदेश

कटघरे में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की काबिलियत

एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट ने मध्यप्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर मुहर लगा दी है। यह अपराध 2020-21 के हैं। इन आकड़ों को देखने के बाद लगने लगा है कि शांति का टापू कहे जाने वाला मध्यप्रदेश अपराधों का गढ़ बन गया है। प्रदेश की शिवराज सरकार में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भले ही इस रिपोर्ट के बाद दलीलें और दावे करते पेश कर रहे हो लेकिन उनके दावों में कोई भी सच्चाई नही है। रिपोर्ट रिपोर्ट के बाद तो निशाने पर नरोत्तम मिश्रा आ गए हैं। रिपोर्ट में बाल अपराध, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और आदिवासी उत्पीड़न के सभी आंकड़े पेश किए गए है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयास धरे के धरे रह गए हैं। भले ही अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार कई अभियान चला रही है। इसके बाद भी प्रदेश में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की वर्ष २०२१ की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल चार लाख 75 हजार 918 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42 हजार अधिक हैं। इनमें 10 फीसदी यानी 30,673 अपराध सिर्फ महिलाओं के साथ ही किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर सर्वाधिक अत्याचार के मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। देशभर में एक साल में हुए कुल अपराधों में मध्यप्रदेश एक पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है।

बाल अपराध, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और आदिवासी उत्पीड़न में अव्वल हुआ राज्य

विजया पाठक

हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट आयी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद मध्यप्रदेश शर्मसार हो गया है। रिपोर्ट के बाद तो कहा जा सकता है कि प्रदेश अब अपराधों का गढ़ बन गया है। पिछले कुछ सालों में सभी क्षेत्रों में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। बाल अपराध, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और आदिवासी उत्पीड़न में राज्य अव्वल हो गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयास धरे के धरे रह गए हैं। भले ही अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार कई अभियान चला रही है। इसके बाद भी प्रदेश में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल चार लाख 75 हजार 918 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42 हजार अधिक हैं। इनमें 10 फीसदी यानी

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की निरंकुशता ने मध्यप्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के लिए नरोत्तम जिम्मेदार है।

30,673 अपराध सिर्फ महिलाओं के साथ ही किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर सर्वाधिक अत्याचार के मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। देशभर में एक साल में हुए कुल अपराधों में मध्यप्रदेश एक पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि मध्यप्रदेश में आज भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बालात्कार, मर्डर, घरेलू हिंसा, जैसी

एनसीआरबी की रिपोर्ट को पढ़ने और देखने के बाद देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी मध्यप्रदेश की इस स्थिति पर खासी नाराजगी व्यक्त की है।

वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट को पढ़ने और देखने के बाद देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी मध्यप्रदेश की इस स्थिति पर खासी नाराजगी व्यक्त की है। सवाल यह है कि पिछले कई सालों से एनसीआरबी की रिपोर्ट पर नजर डाले तो एक भी बार ऐसा कहीं प्रतीत होता नहीं दिख रहा है जब यह कहा जाये कि प्रदेश में आपराधिक मामले नियंत्रण में हैं।

एनसीआरबी के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बोला हमला

मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आंकड़ों ने सरकार के सुशासन की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में औसतन हर 03 घंटे में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना घटती है। जो खुद को मामा कहलवाते हैं, यह उनकी सरकार की शर्मनाक वास्तविकता है। मध्यप्रदेश जो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म में वर्षो से देश में अव्वल है, उस पर लगा यह दाग अभी भी बरकरार है। कमलनाथ ने कहा कि मैं प्रारंभ से ही कहता रहा हूं कि आज प्रदेश में बहन-बेटियों को सबसे ज्यादा सुरक्षा व सम्मान की आवश्यकता है। शिवराज जी की सरकार जनता को गुमराह करने के लिए इनका मंचों पर पूजन तो करती हैं लेकिन वर्षो से इन्हें सुरक्षा व सम्मान देने में यह सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि आत्महत्या के मामले में भी मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। यह शिवराज सरकार के पिछले 16 वर्षो के विकास, सुशासन के दावों की हकीकत है। आज मध्यप्रदेश में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासी वर्ग और दलितों के खिलाफ अत्याचार में भी मप्र एक बार फिर देश में शीर्ष पर आया है। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में एससी-एसटी वर्ग के खिलाफ मामलों में 9.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आत्महत्या के मामले में भी मप्र देश में तीसरे स्थान पर है।

भारत में हर दिन 90 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा

एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल देश में हर दिन कम से कम 90 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। पिछले साल देश में हर दिन कम से कम 90 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। ये मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 04 (पेनेट्रेटिव यौन हमले के लिए सजा) और 06 (गंभीर यौन

मध्यप्रदेश में महिलाओं से अपराध के मामले बढ़े एक स्थान फिसल छठवें स्थान पर पहुंचा

मध्यप्रदेश में महिलाओं से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के साथ घटित अपराध के मामले में मध्यप्रदेश इस वर्ष 30 हजार 673 प्रकरणों के साथ छठवें स्थान पर है। जबकि वर्ष 2020 में यह पांचवें स्थान पर था। दहेज प्रताड़ना के मामले सात हजार 929 सामने आए हैं। देश में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण मध्यप्रदेश में सर्वाधिक तीन हजार 515 हैं। दहेज के लिए हत्या के प्रकरण के मामलों में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2021 में 522 मामले दर्ज हुए हैं। महिलाओं पर हमले के मामले पांच हजार 760 सामने आए हैं। जबकि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में विवेचना करके न्यायालय में प्रस्तुत करने की दर 84 प्रतिशत रही है, जो देश में दूसरे स्थान पर है।

मध्यप्रदेश में बीते राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत, महिलाओं व बेटियों के साथ अपराध को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ शासन द्वारा संपत्ति नष्ट किए जाना शुरू किया गया है। लेकिन असलियत यह है कि एमपी देश का चौथा ऐसा सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर लड़कियों और महिलाओं को शादी के लिए सबसे ज्यादा मजबूर किया जाता है। इतना ही नहीं अपहरण और अन्य तरह से उन्हें ब्लैकमेल तक किया जाता है। अपराध की बात की जाए तो देश में शीर्ष पांच राज्यों में मध्यप्रदेश पांचवें नंबर पर है। नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2019 के द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आया है। सूबे में 2019 में कुल 1626 प्रकरण दर्ज किए गए, इसमें महिलाओं और लड़कियों ने जबरन शादी करने के लिए अपहरण और ब्लैकमेल करने के मामले दर्ज कराए हैं। इसमें कुल 1635 महिलाएं पीड़ित रहीं। सूबे में महिलाओं पर अपराध की स्थिति की बात करें तो साल 2017 में कुल 29,788 मामले सामने आए थे। इसके बाद साल 2018 में इन मामलों में थोड़ी कमी आई थी, जिसमें कि कुल 28,942 केस संज्ञान में आये थे।

बलात्कार में मप्र दूसरे नंबर पर- बलात्कार के मामले में मप्र दूसरे नंबर पर है। यहां एक साल में 6459 केस दर्ज हुए। इस सूची में राजस्थान पहले नंबर पर है। यहां रेप के 6917 प्रकरण दर्ज किए गए।

प्रदेश में 01 साल के भीतर हुए 03 लाख अपराध, 10 प्रतिशत महिलाओं के खिलाफ

देशभर में एक साल में हुए कुल अपराधों में मध्यप्रदेश एक पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में इस साल 3,04,066 केस दर्ज किए गए। इनमें 10 फीसदी यानी 30,673 अपराध सिर्फ महिलाओं के साथ ही किए गए हैं। साल 2020 में यहां 2,83,881 केस दर्ज हुए थे। इस लिहाज से इस साल

उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। 2021 में देश भर में 33,186 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। 3,522 नाबालिग लड़कियों के यौन

महिलाओं के खिलाफ अपराध में 5036 केसों की बढ़ोतरी हुई है। रेप और गैंगरेप के बाद हत्या के केस में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। एक साल में प्रदेश में 35 ऐसे केस दर्ज किए गए, जिसमें पीड़िता के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई। 48 केस के साथ यूपी पहले स्थान पर है। असम में ऐसे 46 केस सामने आए।

इंदौर, ग्वालियर और भोपाल के आंकड़े शर्मसार करने वाले

मध्यप्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वूमन अब अनकंट्रोल होता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार सबसे बुरा हाल इंदौर का है। यहां महिलाओं के खिलाफ सबसे यादा अपराध हो रहे हैं। दूसरा नंबर ग्वालियर का है और तीसरे नंबर पर भोपाल और चौथे पर जबलपुर है।

शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं। यहां महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। ये हाल तब है जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किये हैं। पुलिस आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों में 5251 महिलाएं अपराध का शिकार हुईं। इनमें से दहेज प्रताड़ना के 3121, रेप 1984 और दहेज हत्या 146 हुईं। 10 महीने में इंदौर में सबसे यादा 890 केस दर्ज हुए। इनमें 342 रेप, दहेज हत्या 19, दहेज प्रताड़ना के 529 मामले सामने आए। इसी अवधि में ग्वालियर में 848 केस दर्ज हुए। इनमें 254 रेप, दहेज हत्या 23, दहेज प्रताड़ना के 571 केस हैं. भोपाल में 804 केस दर्ज हुए। इनमें 315 रेप, दहेज हत्या 22, दहेज प्रताड़ना की 467 एफआईआर हुईं। जबलपुर में 804 केस दर्ज हुए। इनमें 192 रेप, दहेज हत्या 14, दहेज प्रताड़ना के 290 मामले सामने आए हैं। सागर में 411, धार में 389, बालाघाट में 381, मुरैना में 364, देवास में 341, राजगढ़ में 327 केस दर्ज किये गए। प्रदेश में पिछले एक साल में महिला अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इस मामले में इंदौर पहले स्थान और भोपाल दूसरे स्थान पर है। साल 2020 में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या 26 हजार 462 थी, जो 2021 में बढ़कर 31 हजार 911 हो गए हैं। साल 2020 की तुलना में 2021 में प्रदेश में महिला अपराधों की संख्या में करीब 05 हजार की बढ़ोत्तरी हुई है। महिला अपराधों के मामलों में इंदौर और भोपाल शहर शीर्ष पर हैं। पुलिस मुख्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक रेप, अपहरण और अन्य मामलों में इंदौर में सबसे यादा मामले दर्ज हुए हैं। इंदौर में पिछले साल महिला अपराध के 2324 मामले सामने आए हैं। इसमें बलात्कार के 379, गैंगरेप के 25, अपहरण 655, छेड़खानी के 497 और दहेज हत्या के 21 मामले हैं। भोपाल में महिला अपराध के पिछले एक साल में 1892 मामले सामने आए। इसमें बलात्कार के 363, गैंगरेप के 09, अपहरण के 349, छेड़छाड़ के 444 और दहेज हत्या के 25 मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में महिला अपराध के 1590 मामले सामने आए। इसमें बलात्कार के 269 मामले, गैंगरेप के 22, अपहरण के 203, छेड़छाड़ के 364 और दहेज हत्या के 26 मामले हैं। जबलपुर में महिला अपराध के कुल 1429 मामले सामने आए। इसमें बलात्कार के 208 मामले, गैंगरेप के 07, अपहरण के 375, छेड़खानी के 412 और दहेज हत्या के 15 मामले हैं।

शोषण की रिपोर्ट करने में मध्यप्रदेश शीर्ष पर था। उसके बाद महाराष्ट्र में 3,480, तमिलनाडु में 3,435 और उत्तरप्रदेश में 2,749 थे। ऐसी 2,093 घटनाओं के साथ कर्नाटक पांचवें स्थान पर रहा। कर्नाटक में 2021 में हर दिन कम से कम पांच

आदिवासियों पर अत्याचार में नंबर वन मध्यप्रदेश

एक तरफ प्रदेश सरकार जनजातियो के संरक्षण की बात कर रही है वहीं, दूसरी तरफ जनजातियों के साथ हुए अत्याचार के मामले में मध्यप्रदेश नंबर वन है। अनसुचित जाति वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित अपराधों के मामले में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। यहां वर्ष 2021 में सात हजार 214 अपराध रजिस्टर्ड हुए। अनसुचित जाति वर्ग से जुड़े मामलों में सजा दिलाने की दर 34.3 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत 28.1 प्रतिशत से अधिक और राज्यों में दूसरे स्थान पर है। अनसुचित जाति वर्ग से जुड़े मामलों में सजा दिलाने की दर 34.3 प्रतिशत रही है।

दलितों, ट्राइबल के खिलाफ अत्याचार में भी अव्वल- प्रदेश ट्राइबल और दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले में भी पिछली बार की तरह इस बार भी अव्वल है। साल 2021 में यहां एससीएसटी एक्ट के तहत 2627 मामले दर्ज हुए। ये 2020 की तुलना में करीब 9.38 फीसदी अधिक हैं। 2020 में 2401 मामले आए थे। दलितों से अत्याचार के कुल 7214 मामले दर्ज हुए। खास बात ये है कि ये चौंकाने वाले आंकड़े उस समय के सामने आए हैं, जब प्रदेश की सरकार खुद आदिवासियों और दलितों के हित के लिए कार्य करने का दावा कर रही है।

नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। मध्यप्रदेश की बात करें तो साल 2020 की तुलना में साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में एक फीसदी का इजाफा हुआ है। साल 2020 में टोटल महिला अपराध 25,640 थे जबकि साल 2021 में 30,673 हो गये। बच्चियों से रेप और पाक्सो एक्ट में देश में मध्य प्रदेश नंबर वन पर है। वहीं टोटल महिला अपराध में यह छठवें नंबर पर है। इन आंकड़ों के हिसाब से हर 03 घंटे में मध्यप्रदेश में एक बच्ची दुष्कर्म का शिकार हो रही है।

अपराधों का लेखा जोखा रखने वाली संस्था नेशनल क्रक्रीइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं के खिलाफ अपराध

उत्तरप्रदेश में देश में दलितों की सबसे अधिक आबादी रहती है। साल 2011 की जनगणना (जिसका उपयोग एनसीआरबी एससी के खिलाफ अपराधों की दर की गणना के लिए करता है) के अनुसार इस राज्य में 04 करोड़ से अधिक दलित थे। पिछले साल, यूपी में ऐसे मामलों में अपराध दर 31.8 दर्ज की गई थी, इसका मतलब है कि राज्य की हर 01 लाख दलितों पर साल 2021 में करीब 31 जाति आधारित अपराध दर्ज किए गए। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की अपराध दर, जो क्रमशः 63.6 प्रतिशत और 61.6 प्रतिशत थी, से काफी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से प्रत्येक राज्य में 01 करोड़ से अधिक की दलित आबादी रहती है। संदर्भ के लिए यह जान लेना जरुरी है कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ राष्ट्रीय औसत अपराध दर इस समुदाय की प्रति 01 लाख आबादी पर 25 अपराध है। मध्यप्रदेश और राजस्थान में अपराध दर इस औसत से दोगुने से भी ज्यादा है। कई अन्य राज्यों ने भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर की अपराध दर दर्ज की, जिनमें से तीन बिहार (35.3), और तेलंगाना (32.6), और ओडिशा (32.4) के हालात उत्तरप्रदेश से भी बदतर हैं। दलितों के खिलाफ औसत से अधिक अपराध दर वाले अन्य राज्य हरियाणा (31.8, यूपी के समान), केरल (31.1), और गुजरात (29.5) थे। इसी तरह मध्य प्रदेश ने भी पिछले पांच वर्षो के औसत (49) की तुलना में दलितों के खिलाफ लगभग प्रति लाख दलित जनसंख्या पर 15 अतिरिक्त अपराध दर्ज किए हैं। 2021 में अगली सबसे बड़ी वृद्धि, पिछले पांच साल के औसत की तुलना में, हरियाणा में हुई, जहां दलितों के खिलाफ अपराध एससी आबादी के प्रति लाख पर 13 से अधिक बढ़ गए थे। 2016-2020 के पांच साल के औसत की तुलना में यूपी में साल 2021 में दलितों के खिलाफ अपराध में 3.6 मामले प्रति लाख की बढ़ोतरी हुई। इसके विपरीत बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में, जहां भी जाति-आधारित अपराधों की उच्च दर रही है, पिछले पांच वर्षो के औसत की तुलना में साल 2021 में अपराध दर में वास्तविक रूप में प्रति लाख दलित आबादी पर लगभग 05 अपराध की कमी आई है।

मामले में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 2021 में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध की दर (प्रति 1 लाख जनसंख्या पर घटनाओं की संख्या) 2020 के 56.5 प्रतिशत से बढ़कर 64.5 प्रतिशत हो गई है। ये बढ़ोत्तरी 15.8 फीसदी की है, जो महिला सुरक्षा के तमाम वादों और इरादों से इतर एक अलग सच्चाई बयान करती है। साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,71,503 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,28,278 हो गया। इनमें से अधिकांश मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (31.8 प्रतिशत) के रहे। उसके बाद महिलाओं पर

गृहमंत्री अमित शाह की नाराजगी और नरोत्तम मिश्रा की निरंकुशता

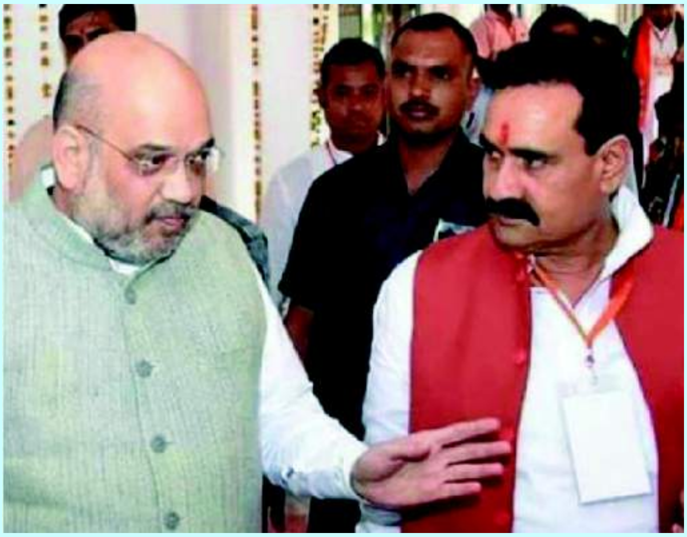

पिछले दिनों भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट कहां था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और दुरस्त करने की आवश्यकता है। यहां आपराधिक मामले निरंतर बढ़ रहे हैं, इन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट आने के बाद शाह ने मध्यप्रदेश सरकार के गृह विभाग पर बुरी तरह से नाराजगी व्यक्त की। सूत्रों के अनुसार शाह ने यह तक भी कह दिया है कि अगर नरोत्तम मिश्रा अपराध पर नियंत्रण लगाने में असफल हो रहे हैं तो सरकार को इनका कोई विकल्प ढूंढना शुरू कर देना चाहिए।

बेफिजूल की सफाई देने में आगे नरोत्तम- एनसीआरबी की रिपोर्ट आने के बाद जब विपक्ष ने शिवराज सरकार को घेरना शुरू किया तो सफाई देने सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा आये और उनका बयान सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे मानों ये प्रदेश में हो रहे आपराधिक घटनाओं से पूरी तरह से अंजान है। इन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं है कि प्रदेश में रोजाना आपराधिक घटनाएं हो रही है।

मुख्यमंत्री का चुप्पी साधना समझ के परे- प्रदेश की खस्ताहाल होती कानून व्यवस्था पर अब भी प्रदेश के मुखिया की चुप्पी समझ के परे है। प्रदेश के गृहमंत्री से भी अब तक उन्होंने कोई सवाल-जबाव नहीं किये और न ही उन्हें इस संबंध में कोई नोटिस जारी करवाया। जबकि मुख्यमंत्री को स्पष्ट निर्देश देते हुए नरोत्तम मिश्रा से तुरंत गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस लेते हुए कुछ समय के लिए वनवास में भेज देना चाहिए। प्रदेश में आपराधिक मामलों को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी प्रदेश की शिवराज सरकार ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को दी है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ऐसे निरंकुश गृहमंत्री हैं, जिनसे प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाले नहीं संभल रही। पूरे समय विपक्षी दलों के नेताओं पर टीका-टिप्पणी करना, मीडिया में बने रहने के लिए उलूल-जुलूल विषयों पर बयानबाजी करना ही इनकी प्राथमिकता है। अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में जहर घोल दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब विभागीय मंत्री ही विभाग की मिट्टी पलीत करने में जुटे हुए हैं तो अपराध भला कैसे नियंत्रित होंगे। सूत्रों के अनुसार नरोत्तम मिश्रा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते। उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले रखी है और पुलिस के आला अधिकारी महज केवल एक कठपुतली की तरह काम करने को मजबूर हैं। आये दिन महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। जब प्रदेश का पुलिस प्रशासन ही पूरी तरह से निरंकुश हो जायेगा तो गुंडे, बदमाशों के हौंसले तो बुलंद होना लाजमी है।

शील भंग करने के इरादे से हमला (20.8 प्रतिशत), अपहरण (17.6 प्रतिशत) और बलात्कार (7.4 प्रतिशत) के मामले रहे। 2021 में दर्ज मामलों की वास्तविक संख्या के मामले में रिपोर्ट में उत्तरप्रदेश (यूपी) को शीर्ष पर (56,083) रखा गया है। हालांकि

मध्य प्रदेश और राजस्थान में दलितों के खिलाफ अपराध दर है सबसे ज्यादा और ये हैं इसके कारण

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी किये गए क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तरप्रदेश ने एक बार फिर से पूरे भारत में अनुसूचित जातियों, या दलितों, के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज करने का संदिग्ध ख़िताब हासिल किया है। लेकिन, इन आंकड़ों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2021 में प्रत्येक 01 लाख दलित आबादी के लिए राजस्थान और एमपी में 60 से अधिक अपराध दर्ज किए और यूपी ने 25 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले प्रति लाख दलित आबादी पर 31 ऐसे मामले दर्ज किए.पर थोड़ी गहराई से नजर डालने से पता चलता है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान कुछ और परेशान करने वाले रुझान पेश करते हैं। इन दोनों राज्यों ने साल 2021 में दलितों के खिलाफ उच्चतम अपराध दर (प्रति लाख जनसंख्या के लिए दर्ज मामले के आधार पर) दर्ज किए, जो यूपी से काफी आगे और ऐसे मामलों के राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी अधिक थे। साल 2016 से 2020 तक दलितों के खिलाफ हुए अपराधों की पिछले पांच साल की औसत दर की गणना करने के लिए एनसीआरबी डेटा का उपयोग किया और फिर इसकी तुलना 2021 के आंकड़ों से की। यहां भी राजस्थान और मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति के सदस्यों के खिलाफ अपराध दर में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई दी। अनुसूचित जाति के खिलाफ किए गए अपराधोंअत्याचारों की गिनती के लिए एनसीआरबी के आंकड़े में केवल वे ही मामले शामिल हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जिसे एससीएसटी एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, के तहत दायर किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सिर्फ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दायर किए गए मामलों की गिनती नहीं करता है, क्योंकि उन मामलों में अनुसचित जाति के ही किसी सदस्य द्वारा किसी और एससीएसटी के खिलाफ किये गए अपराध का उल्लेख होता है। कुल मिलाकर एनसीआरबी की इस ताजातरीन रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने साल 2021 में हर घंटे दलितों के खिलाफ छह अपराध दर्ज किए, पिछले साल ऐसे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 50,900 हो गई, जो 2020 में 50,291 थी। कुल मामलों की संख्या के आधार पर उत्तरप्रदेश ने दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध के मामले 13,146 दर्ज किए, जो कि 2021 में पूरे देश में घटी कुल ऐसी घटनाओं का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। इसके बाद राजस्थान (7,524), मध्यप्रदेश (7,214) और बिहार (5,842) थे। इन राज्यों में से यूपी, राजस्थान और एमपी में 2020 की तुलना में अधिक मामले देखे गए, लेकिन बिहार में ऐसे मामलों में गिरावट देखी गई। हालांकि इसकी एक अधिक सटीक तस्वीर, अपराधों की कुल संख्या के बजाय अपराध दर से प्राप्त की जा सकती है।

वहां अपराध की दर 50.5 प्रतिशत से कम है। महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज करने वाले अन्य राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं। वहीं, पिछले तीन सालों की तरह इस साल भी नगालैंड में महिलाओं के खिलाफ सबसे कम अपराध दर्ज हुए।

जारी किए आंकड़ों से बढ़ा विवाद, विपक्ष हुआ हमलावर

मध्यप्रदेश में चुनावी साल के ठीक पहले अपराधों को लेकर भाजपा व कांग्रेस

हर दिन देश में कम से कम 90 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार

इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल देश में हर दिन कम से कम 90 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। ये मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 4 (पेनेट्रेटिव यौन हमले के लिए सजा) और 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। 2021 में देश भर में 33,186 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। 3,522 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की रिपोर्ट करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर था। उसके बाद महाराष्ट्र में 3,480, तमिलनाडु में 3,435 और उत्तर प्रदेश में 2,749 थे। ऐसी 2,093 घटनाओं के साथ कर्नाटक पांचवें स्थान पर रहा। कर्नाटक में 2021 में हर दिन कम से कम पांच नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। वहीं आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में दिल्ली में हर दिन औसतन दो बच्चियों से बलात्कार हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में बलात्कार की उच्चतम दर 16.4 प्रतिशत राजस्थान में देखी गई, जो जहां पिछले साल दर्ज किए गए 6,337 मामलों के साथ वास्तविक अपराधों की संख्या में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद यूपी, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र रहे, जहां पिछले साल 2,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर पिछले साल देश में बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले पांच वर्षो में 2018 के 33,977 मामलों की तुलना में

के बीच रार मच गई है। इसकी वजह है एनसीआरबी ने द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ें। इन आंकड़ों में कई तरह के अपराधों के मामले में प्रदेश में बेहद खराब स्थिति बताते हुए देश में पहले नंबर पर बताया गया है। इसके बाद से की विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर हमलावर की मुद्रा में आ गई है, तो वहीं सत्तारुढ़ दल भाजपा और प्रदेश सरकार की ओर से मोर्चा

राज्यवार महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध

राज्य	कुल केस	महिला	प्रतिशत
उत्तरप्रदेश	3,57,905	56,083	16 प्रतिशत
राजस्थान	2,14,552	40,738	19 प्रतिशत
महाराष्ट्र	3,67,218	39,526	11 प्रतिशत
प. बंगाल	1,57,498	35,884	23 प्रतिशत
ओडिशा	1,24,956	31,352	25 प्रतिशत
मध्यप्रदेश	3,04,066	30,673	10 प्रतिशत

मामूली गिरावट को दर्शाता है।

एनसीआरबी साल 2017 से सामूहिक बलात्कार के साथ हत्या के मामलों का रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। साल 2021 में ऐसे 284 मामले सामने आए। इतने ही मामले 2019 में भी देखे गए थे। 2020 में ऐसी 218 घटनाएं हुई थीं। इस तरह के सबसे अधिक 48 मामले पिछले साल यूपी में देखने को मिले, इसके बाद असम में 46 ऐसे मामले सामने आए। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड में पिछले साल इस श्रेणी में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले साल 28,000 से अधिक महिलाओं का अपहरण कर विवाह के लिए मजबूर किया गया, जिसमें 12,000 नाबालिग शामिल थीं। ऐसे मामलों की सर्वाधिक संख्या यूपी (8,599) और उसके बाद बिहार (6,589) में दर्ज की गई। पिछले साल दहेज हत्या के 6,589 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें सबसे अधिक ऐसी मौतें यूपी और बिहार में दर्ज की गई थी।

हर साल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर विलाप- 2021 में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत देश में केवल 507 मामले दर्ज किए गए, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों का 0.1 प्रतिशत है। ऐसे सबसे ज्यादा मामले (270) केरल में दर्ज किए गए। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में अपहरण के सबसे अधिक 5,475 मामले सामने आए थे जबकि पिछले साल 4,011 मामले सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक पुलिस 5,274 अपहृत लोगों को बचा पाई, जिनमें 3,689 महिलाएं शामिल हैं। अपहृत किए गए 17 लोग मृत पाए गए, जिनमें आठ महिलाएं भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट हर साल आती है और हर साल हम महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर विलाप की कहानी दोहराते हैं। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ोतरी हुई, हर दिन इतनी महिलाएं और नाबालिग लड़कियां दुष्कर्म का शिकार हुईं, हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या का ग्राफ इन महानगरों में बड़ा, तो कभी ये राज्य महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित हैं इत्यादि। लेकिन इससे महिला सुरक्षा की

सम्हालने के लिए पुलिस अफसरों को लगाया गया है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार कानून व्यवस्था के मामले में हर मोर्चे पर विफल हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2021 के लिए जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें आदिवासियों पर अत्याचार में मप्र पहले स्थान पर है।

नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के

समस्या का समाधान नहीं होता। ना ही विश्वगुरु बनने की चाहत रखने वाले भारत में महिलाओं की स्थिति बदलती है।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा, उनमें महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा था। पार्टी ने अपने मैनिफ़ेस्टो में और प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में कई वायदे किए। लेकिन अब सत्ता में लगभग आठ साल गुजारने के बाद भी वो वादे केवल नारों तक ही सिमट कर रह गए और महिलाओं के खिलाफ अपराध धड़ल्ले से बढ़ते चले गए। ये विडंबना ही है कि यूपीए की सरकार में निर्भया के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़िया भेजने वाली स्मृति ईरानी आज खुद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और बिलकिस बानो के अपराधियों पर चुप्पी साधे हुए हैं।

लगातार बढ़े महिलाओं के खिलाफ अपराध- वर्ष 2021 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,28,278 मामले दर्ज किए गए। इनमें अपराध की दर (प्रति एक लाख आबादी पर) 64.5 फीसदी रही। आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे अपराधों में आरोपियों पर आरोप पत्र दायर करने की दर दर 77.1 फीसदी थी। बात करें वर्ष 2020 की तो तब महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों की संख्या 3,71,503 और 2019 में 4,05,326 दर्ज की गई थी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दुष्कर्म, दुष्कर्म व हत्या, दहेज हत्या, एसिड हमले, आत्महत्या के लिए उकसाना, अपहरण, जबरन शादी, मानव तस्करी, ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे अपराध शामिल हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले यूपी में- 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश (56,083) में दर्ज किए गए, उसके बाद राजस्थान (40,738), महाराष्ट्र (39,526), पश्चिम बंगाल (35,884) और ओडिशा में 31,352 दर्ज किए गए। हालांकि, महिलाओं के खिलाफ अपराध दर के आधार पर तुलना करें तो असम 168 फीसदी के साथ शीर्ष पर है। वहीं, दिल्ली 147 फीसदी के साथ दूसरे व ओडिशा 137 फीसदी के साथ तीसरे नंबर पर रहा। हर साल आने वाली एनसीआरबी की रिपोर्ट से देश में अपराधों पर नियंत्रण में मदद मिलती है। इसके

आधार पर सुरक्षा एजेंसियां संबंधित क्षेत्रों में अपराध पर लगाम लगाने के उपाय करती हैं।

दहेज हत्या में उत्तरप्रदेश अव्वल- देशभर में दहेज हत्या में उप्र पहले नंबर पर है। यहां 2222 बेटियों को दहेज के लिए मार दिया गया। बिहार में 1000 तो मप्र में 522 बेटियों की जान दहेज के लिए ले ली गई। दहेज प्रताड़ना के सबसे अधिक 19952 केस पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में मप्र तीसरे पायदान पर है। यहां 7214 केस दर्ज किए गए।

मामले में नम्बर एक पर है मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज हो रहे हैं। लगातार दूसरे साल एमपी बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए है। 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 19,173

हत्या में यूपी पहले नंबर पर- हत्या के मामले में उप्र आगे है। यहां 2021 में हत्या के 3717 केस दर्ज हुए, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। यहां 2330 लोगों की हत्या हुई। मप्र में हत्या के 2034 केस सामने आए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की कायमी और कोर्ट में चालान पेश करने में मप्र देश में दूसरे नंबर पर है। राज्य में चार्जशीट पेश करने की दर 84 फीसदी है। पश्चिम बंगाल में 94 फीसदी मामलों में चार्जशीट पेश की गई।

महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर दिल्ली- महिलाओं के केस को लेकर बात करें तो देशभर में दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। यहां 2020 में महिलाओं के खिलाफ 9782 केस दर्ज हुए थे, जो 2021 में 40 फीसदी बढ़कर 13,892 हो गए हैं। ताजा यानी 2021 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रोजाना औसतन दो नाबालिग लड़कियां अपराधियों की हवस का शिकार हुई हैं।

महानगरों में दिल्ली सबसे असुरक्षित- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ क्राइम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, उसकी 32 फीसदी घटनाएं अकेले राजधानी में होती हैं। सभी 19 मेट्रो सिटीज में साल 2021 में महिलाओं के साथ क्राइम के कुल 43,414 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 13,982 मामले अकेले दिल्ली में दर्ज हुए। दिल्ली के बाद अगला नंबर है मुंबई और बेंगलुरु का। इन दोनों महानगरों में भी 2020 के मुकाबले 2021 में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और क्रीइम की घटनाओं में आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ोतरी हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2021 में औरतों के साथ क्राइम के कुल 5,500 मामले दर्ज किए गए और बेंगलुरु इस तरह के कुल 3,000 मामले दर्ज हुए। सभी मेट्रो सिटीज में महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम का 12.7 फीसदी अकेले मुंबई में हो रहा है और 7.2 फीसदी बेंगलुरु में। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि महिलाओं के साथ होने वाले क्रीइम में सबसे ज्यादा योगदान देश की राजधानी का ही है।

केस दर्ज किए गए है जो कि देश में सबसे अधिक है। जानकारी के अनुसार यहां साल दर साल बच्चों के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि दर्ज की है और पिछले एक दशक (2011-2021) में बच्चों के खिलाफ अपराध में 337 प्रतिशत फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। मध्यप्रदेश में 2011 में कुल मामलों की संख्या 4,383 थी जो 2021 में 19,173 हो गई है। रिपोर्ट

के अनुसार प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध के हर दिन 52 से अधिक मामले दर्ज होते हैं जो कि देश में सबसे अधिक है। इतना ही नहीं राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

बच्चों के अपहरण के मामले में एमपी का औसत राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। वहीं 2020 के तुलना में 6.2 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं राज्य में बच्चों के खिलाफ कुल अपराध के मामले में 31.7 फीसदी मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में औसतन हर तीन घंटे में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है। 2021 में प्रदेश में बच्चियों के साथ रेप के 3515 मामले दर्ज हुए। जबकि देश में यह आंकड़ा 33,036 है। वहीं बच्चियों से रेप के मामले में 2021 में *3512 केस में से 2499 लापता से जुड़े* केस थे जिनमें रेप की धारा बढ़ाई गई और प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान चलाकर लापता बच्चियों की खोज की गई।

प्रदेश में औसतन लगभग हर तीन घंटे में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। यह चिंताजनक नहीं बल्कि भयावह स्थिति है। साल 2019, 2020 और 2021 से सतत मध्यप्रदेश नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में देश में नम्बर एक पर आ रहा है।

बच्चियां शोषण की शिकार- नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न में मप्र पहले नंबर पर है। एक साल में यहां 3515 बच्चियां शिकार हुईं। 2020 में आंकड़ा 3259 था। 3458 केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। हालांकि मप्र में नाबालिगों के साथ हुए बलात्कार के कुल केसों में 2499 वे हैं, जिनमें गुमशुदगी के *बाद बरामदगी की गई। एनसीआरबी द्वारा* जारी की गई हालिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछली बार की तरह इस बार भी बच्चों से ज्यादती के मामले में मध्यप्रदेश अव्वल रहा है। साल 2021 में देशभर में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 33,036 मामले सामने आए। इनमें सिर्फ मध्यप्रदेश में ही बच्चियों से दुराचार के 3515 मामले दर्ज किए गए। जबकि कुल ज्यादती के मामलों पर गौर करें, जिनमें नाबालिग के साथ बालिग, बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें प्रदेश में 6462 केस रजिस्टर्ड हुए।

हर रोज 08 बच्चियां हो रहीं हवस का शिकार- ऐसे में अगर औसतन हर 24 घंटे का हिसाब लगाया जाए तो मध्यप्रदेश में रोजाना 08 बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हुई हैं। आपको याद हो कि, प्रदेश में साल 2020 के दौरान भी यही हालात थे। इस

साल प्रदेशभर में दुष्कर्म के कुल 5598 केस दर्ज किए गए थे, इनमें से 3259 केस सिर्फ नाबालिग बच्चियों से दुराचार के मामले में दर्ज किए गए थे। खास बात ये है कि तब भी देशभर में मध्य प्रदेश ही इस मामले में अव्वल था। इस हिसाब से गौर करें तो गौर करें तो आंकड़े सामने आने के बावजूद भी प्रदेश की कानून व्यवस्था में इन घटनाओं की रोकथाम को लेकर कोईइ ठोस कदम नहीं उठाये हैं। यही वजह है कि यहां अपराधियों के हौंसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं।

प्रतिदिन औसतन 23 बेटियों का अपहरण- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक प्रदेश में 10 हजार 66 बेटियों का अपहरण हुआ है। बेटियों के खिलाफ अपराध में प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भोपाल है। वहीं मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार में प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के प्रश्न के लिखित जवाब में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 2017 से 2021 यानि 5 वर्षो में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 19.81प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, अकेले वर्ष 2021 में 32,802 मामले अलग अलग धाराओं में दर्ज किए गए। मध्यप्रदेश में महिला अपराध पर रोकथाम के लिए 52 महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई हैं। हालांकि राज्य सरकार ऑपरेशन मुस्कान जैसे अभियान चलाती है, ताकि अपहृत लड़कियों को खोजा जा सके। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में महिला सुरक्षा विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। सरकार के दावे अनेक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं को मध्यप्रदेश के बेटे, बेटियों के मामा कहते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध समाज और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है।

मध्यप्रदेश में भी होती है लड़कियों की खरीद फरोख्त

शाजापुर की यह खबर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं क्योंकि मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों से नाबालिग लड़कियों को लाकर जिस्म फरोशी एवं घर बसाने के नाम पर दलाली करने का बड़ा मामला सामने आया है। दलाल इस सौदे के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। बेहद हैरान कर देने वाला यह मामला गुजरात, अहमदाबाद निवासी बलौदा 17 वर्षीय किंजल और वर्षा दो बहनों का है। किंजल छोटी एवं वर्षा बड़ी बहन है। दोनों को यहां पर घर बसाने की बात कहकर लाया गया। वर्षा का तो सौदा 50 हजार रुपए में बलदेव सिंह एवं उसकी पत्नी बबली द्वारा कर दिया गया, लेकिन जब छोटी बहन किंजल की बिकने की बारी आई तो उसने मनाकर दिया उसे क्या पता था कि मना करना उसकी मौत का कारण बन जाएगा 17 वर्षीय किंजल के साथ 4 दिनों तक दुष्कर्म किया फिर सौदा नहीं जमा तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दलाल बलदेव एवं पत्नी बबली ने भूरिया उर्फ भंवरसिंह निवासी धतुरिया किंजल को बेचना चाहा और उसके साथ दुष्कर्म 4 दिनों तक दुष्कर्म भी किया। जब किंजल ने बिकने से मना किया तो तीनों ने मिलकर बोलाई के जंगल में ले जाकर उसकी पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या कर दी एवं मौके से फरार हो गए।

रीवा में नाबालिग लड़की से रेप

मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाने का है, जहां अष्टभुजी माता के मंदिर में किशोरी दोपहर में अपने एक दोस्त के साथ दर्शन करने आई थी। उसी समय कुछ युवक वहां पहुंच गए और उन्हें धमकाने लगे। आरोपी किशोरी को घसीट ले गए है और एक-एक कर उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बाद किशोरी डरी हुई थी और थाने में जाने से हिचक रही थी लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद वह मामला दर्ज कराने को तैयार हुई। किशोरी से गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हुए आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल व पायल भी छीन लिया था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की संख्या 6 बताई जा रही है।

भारत जोड़ो यात्रा

रंग ला रही पूर्व सीएम कमलनाथ की मेहनत

राहुल गांधी की यात्रा से एक बार फिर पुनर्जीवित होगी कांग्रेस

07 सितम्बर 2022 से कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की 150 दिनों की 3570 किलोमीटर लम्बी यात्रा को कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा जनसम्पर्क अभियान कहा जा सकता है। इस यात्रा का उद्देश्य उन तमाम लोगों के बीच विश्वास पैदा करना है, जिन्होंने संकट झेला है। यात्रा के दौरान होने वाली रैलियों में अस्तित्व की समस्या पर प्रकाश डाला जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की गिरती साख को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए संजीवनी के रूप में कार्य कर सकती है। देश की राजनीतिक इतिहास में यह यात्रा कांग्रेस के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है। राहुल की यात्रा के दोहरे उद्देश्य हो सकते हैं। पहला यह कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए राहुल पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं में जान फूंक सकते हैं। यह चुनाव पार्टी की किस्मत का निर्णय कर सकते हैं। दूसरा यह कि पार्टी में विद्रोह ने पार्टी कार्यकताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये लोग अब राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना फिर से भरोसा जता सकते हैं।

मध्यप्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल मचा गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा

विजया पाठक

वर्तमान समय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश में चल रही है। यहां भी कार्यकर्ताओं में यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी टीम ने यात्रा को लेकर पहले से जो तैयारियां की थी और मेहनत की है उससे यात्रा की सफलता प्रदर्शित हो रही है। यात्रा को लेकर कमलनाथ की टीम ने जो मेहनत की है वह रंग ला रही है। यात्रा में उमड़ती हजारों की भीड़ बता रही है कि प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्वी में मजबूत स्थिति में है। भारत जोड़ो यात्रा को मध्ययप्रदेश में अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, जिसका जिक्र खुद राहुल गांधी ने किया था। यात्रा की कामयाबी से यही लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर देश में, प्रदेश में पुनजीर्वित होगी। जिस बात की चिंता अब बीजेपी नेताओं के चेहरे पर देखी जा सकती है।

बेहतर होगा लोगों के हित से जुड़े मुददे उठाए राहुल गांधी

अब तक हुई सभाओं में आम आदमी से जुड़े विषय के अलावा राहुल गांधी के भाषण में भाजपा पर तंज, नरेन्द्र मोदी सरकार की नीतियां आदि पर प्रहार देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मेरा मानना है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी आम आदमी के हितों से जुड़े मुददों को भी उठाए जाने की आवश्यथकता है। आज देश में बेरोजगारी, मंहगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों, कोविड-19 के बाद संघर्ष कर रहे छोटे उद्योगों, किसानों के अस्तित्व की समस्या जैसे विषयों से सरकार को अवगत कराना चाहिए और जनता के लिए संघर्ष करना चाहिए। हम करीब से देखे तो राहुल के भाषण की तैयारियों में और गहराई की आवश्यकता है। यानि भाषणों के बिंदुओं में इस बात को समझना होगा कि चुनाव

जनता से जुड़े मुद्दों पर जीते जाते हैं। वीर सावरकर और आरएसएस के खिलाफ बोलना और उन्हें भारत का दुश्मन बताना विपक्ष को राहुल गांधी पर हावी होने के अवसर देता है। वीर सावरकर और आरएसएस को देश के ज्या दातर लोग गलत नहीं मानते हैं।

यात्रा में हो रही आदिवासियों के हकों की बात

मध्यरप्रदेश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट है वह प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में है। बुरहानपुर से शुरू हुई यात्रा ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों से गुजर रही है। निश्चित ही इस यात्रा से आदिवासियों के हकों की बात की जा रही हैं। राहुल गांधी भी अपने एक भाषण में आदिवासियों को देश का असली मालिक बता चुके हैं और यात्रा के दौरान राहुल गांधी टंटया मामा, बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर पुष्पांजिलि अर्पित कर चुके हैं। साथ ही भाषणों में आदिवासियों का देश की आजादी और बलिदानों को बताना नहीं भूलते हैं। निश्चित ही यात्रा से आदिवासियों का कांग्रेस के प्रति झुकाव होगा, जो आगामी चुनाव में लाभदायक साबित होगा। इससे पहले आदिवासी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं उन्हें कांग्रेस ने मान सम्माकन दिया है।

यात्रा होगी कांग्रेस के लिए संजीवनी

एक अरसे के बाद देश की सबसे पुरानी और अभी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे देश की राजनीति को नयी दिशा मिल सकती है। साथ ही जनाधार हासिल करने के संकट से गुजर रही कांग्रेस के लिए यह संजीवनी साबित हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का है। इसके माध्यम से राहुल जमीनी स्तर पर लोगों के साथ संबंध को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। 07

सितम्बर 2022 से कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की 150 दिनों की 3570 किलोमीटर लम्बी यात्रा को कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा जनसम्पर्क अभियान कहा जा सकता है। इस यात्रा का उद्देश्य उन तमाम लोगों के बीच विश्वास पैदा करना है, जिन्होंने संकट झेला है। यात्रा के दौरान होने वाली रैलियों में अस्तित्व की समस्या पर प्रकाश डाला जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की गिरती साख को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए संजीवनी के रूप में कार्य कर सकती है। देश की राजनीतिक इतिहास में यह यात्रा कांग्रेस के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है। राहुल की यात्रा के दोहरे उद्देश्य हो सकते हैं। पहला यह कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए राहुल पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं में जान फूंक सकते हैं। यह चुनाव पार्टी की किस्मत का निर्णय कर सकते हैं। दूसरा यह कि पार्टी में विद्रोह ने पार्टी कार्यकताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये लोग अब राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना फिर से भरोसा जता सकते हैं।

कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में अहम है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा

राहुल गांधी को दक्षिण के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति ही सुहावनी लग रही है, 2024 से पहले वहां बीजेपी से बदला लेने का एक मौका तो है ही। वैसे असली हिसाब-किताब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से करने का इरादा होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश पहुंचने के बाद भरी पूरी लगने लगी है। ऐसा हल्का एहसास कर्नाटक में भी हुआ था, जब सोनिया गांधी ने यात्रा में राहुल गांधी के साथ मार्च किया था, लेकिन तभी से हर निगाह प्रियंका गांधी वाड्रा को खोज रही थीं और आखिरकार इंतजार खत्म हुआ जब यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा के अब तक यात्रा से दूर रहने की वजह हिमाचल प्रदेश चुनाव में उनकी व्यस्तता बतायी गयी थी, जबकि खबर ये भी रही कि सोनिया गांधी के अगले ही दिन वो कर्नाटक में ही यात्रा में शामिल होने

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश पहुंचने के बाद भरी पूरी लगने लगी है। ऐसा हल्का एहसास कर्नाटक में भी हुआ था, जब सोनिया गांधी ने यात्रा में राहुल गांधी के साथ मार्च किया था।

वाली थीं। वैसे मीडिया में जो कवरेज मध्यप्रदेश में मिला है, कर्नाटक में कहां संभव था और प्रियंका गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा को छप्पर फाड़ समर्थन दिया है। राहुल गांधी के स्वागत में वो अकेले नहीं बल्कि पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान के साथ पहुंची हैं। हो सकता है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को मध्यप्रदेश में यात्रा के पड़ावों पर सोनिया गांधी की कमी खल रही हो, लेकिन एक साथ पूरे गांधी परिवार को देखने का मौका तो काफी देर बाद मिला है। पहले ऐसा नजारा अमेठी और रायबरेली में चुनावों के दौरान ही देखने को मिला करता रहा।

वाड्रा परिवार के अलावा यात्रा में सचिन पायलट की मौजूदगी ने भी सबका

ध्यान खींचा है और उसकी चर्चा गुजरात चुनाव में व्यस्त अशोक गहलोत की राजनीति से जोड़ कर होने लगी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ को तो शुभ मौके का इंतजार रहा ही होगा, दिग्विजय सिंह को बड़े दिनों पर घर लौटना खुशगवार ही लगा होगा। मौजूदगी तो कन्हैया कुमार ने भी दर्ज करायी है, जिनके बारे में यात्रा के प्रचार प्रसार का काम देख रहे जयराम रमेश कह चुके हैं कि राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय कन्हैया कुमार ही पूरे यात्रा में नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार की काफी डिमांड बतायी जा रही है। मध्यप्रदेश में कांग्रेसियों की भीड़ देख कर गदगद राहुल गांधी खुशी से उछल उठे। और कहने लगे कि मध्यप्रदेश ने पहले ही दिन महाराष्ट्र की यात्रा को हरा दिया। बोले मैं मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को ए ग्रेड देता हूं। दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने यात्रा को ऑर्गनाइज किया, साथ दिया। यात्रा के पड़ावों पर राहुल गांधी बीच बीच में छोटे छोटे किस्से या लोगों से हुआ बातचीत के अंश भी सुनाते रहते हैं, वे कहते है कि कमलनाथ जी ने मुझसे कहा कि आप थकते नही है? मैंने कहा दो हजार

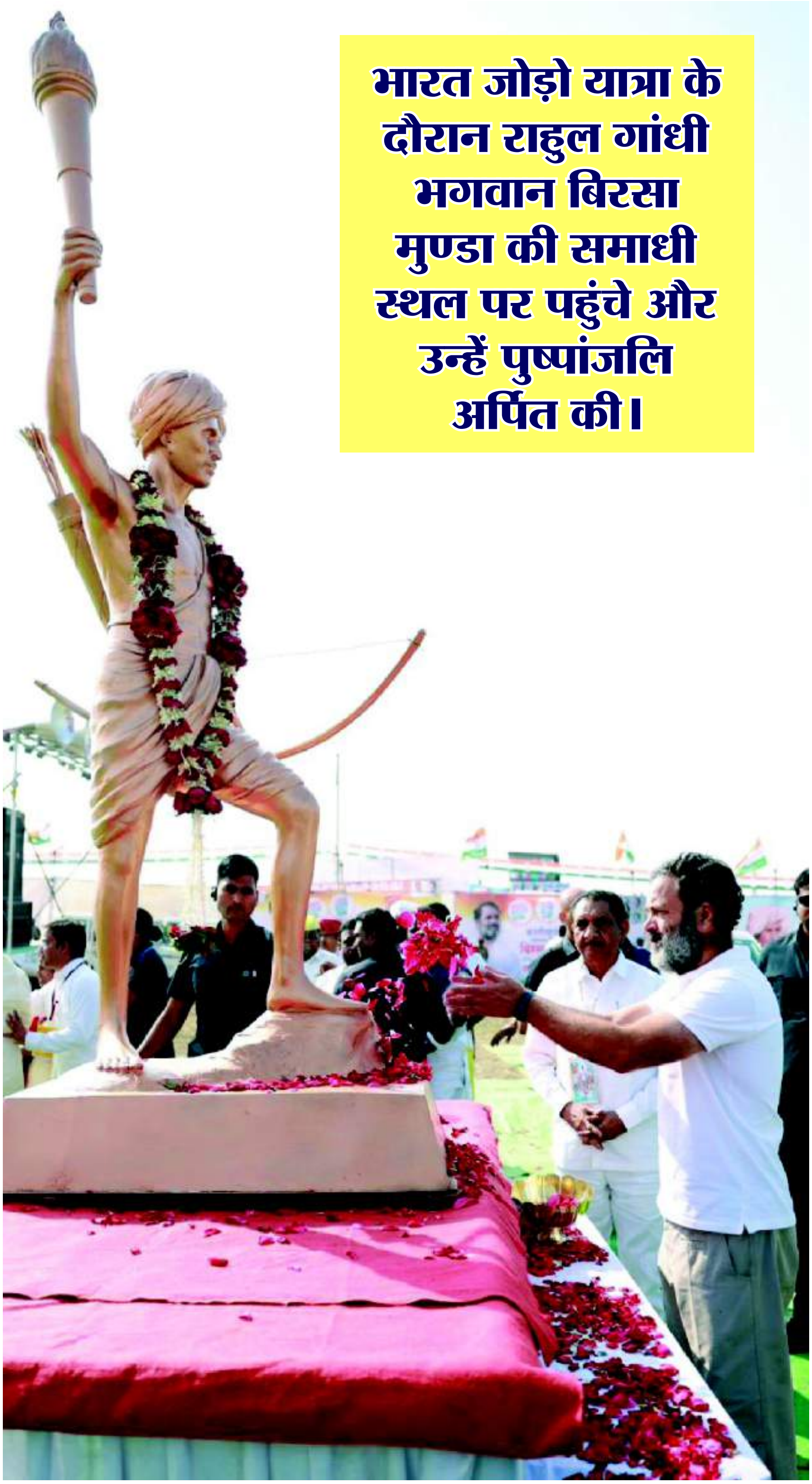

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भगवान बिरसा मुण्डा की समाधी स्थल पर पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

किलोमीटर चला हूं पर थका नहीं। बिल्कुल थका नहीं। सुबह उठता हूं। छह बजे, जिस तेजी से चलता हूं, उससे ज्यादा स्पीड से रात आठ बजे चलता हूं। यात्रा में हम आठ घंटे चलते हैं। और न थकने का राज भी बताया, जिसमें निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम नजर आया। बोले, मैं ज्यादा टाइम चुप रहता हूं। मैं आपसे दो-तीन सवाल पूछता हूं, 15 से 20 मिनट बोलता हूं। मतलब, आठ घंटे आपके मन और 15 मिनट मेरे मन की बात चलती है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद समझाने के लिए राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी को निशाना बनाया और ये भी समझाया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों और कैसे गिर गयी। ये बताने का अंदाज भी ऐसा रहा कि राहुल गांधी के निशाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नजर आ रहे थे। राहुल गांधी का कहना रहा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गये। करोड़ों रुपये खर्च करके हमारे 20-25 विधायक खरीद लिये गये और सरकार बना ली। और फिर जो बातें कही, ऐसा लगा जैसे 2018 के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक रहे हों, हमने सड़क पर उतरकर यात्रा करने का फैसला किया। कुछ विधायकों को खरीद कर बीजेपी ने गलतफहमी पाल ली कि हमें लोगों के दिलों से दूर कर दिया। रुपयों में ईमान बिकता होगा। प्यार और विश्वास नहीं। जनता खुद जवाब देगी।

बदले का मौका तो है! पहले दिन मध्यप्रदेश में राहुल गांधी ने करीब 27 किमी की यात्रा की है और बुरहानपुर की सार्वजनिक सभा में पहली बार अपने पुराने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी निशाना बनाया, लेकिन बगैर नाम लिये ही। सिंधिया समर्थक विधायकों को भ्रष्ट बताकर। ये वे विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में चले

गये थे और उनमें से बहुतों मंत्री बना दिया गया था। विधायकों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुए तो वे बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंच गये।

राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश में साल भर पहले ही चुनावी रैली शुरू कर दी है

मध्यप्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दाखिल होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनावी एक्शन प्लान की तरफ इशारा तो किया ही हैं। भले ही अब भी कॉलेज के जमाने के अपने खास दोस्त सिंधिया का खुलकर नाम नहीं ले पा रहे हों, लेकिन भ्रष्ट विधायकों का जिक्र कर टारगेट तो सिंधिया को ही किया है। ये तो हर किसी को समझ में आता है। ठीक पांच साल बाद कांग्रेस मध्यप्रदेश के मैदान में वैसे ही एंट्री ले सकती है। जैसे 2017 में लिया था। सत्ता विरोधी फैक्टर तो एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ काम करेगा। बीजेपी में भी शिवराज सिंह चौहान के ही खिलाफ होगा। हो सकता है बीजेपी चुनावों से पहले उत्तराखंड और गुजरात और त्रिपुरा जैसे प्रयोग मध्यप्रदेश में भी करे और शिवराज सिंह चौहान को बीएस येदियुरप्पा जैसी भूमिका में लाया जाये, बशर्ते मार्गदर्शक मंडल भेजने का अभी कोई इरादा न हो तो। मध्यप्रदेश में बीजेपी की तरफ से एक दावेदार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे ही। हिमंत बिस्वा सरमा के मिसाल बनने के बाद सिंधिया को इतनी उम्मीद तो करनी ही चाहिये, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिये कि अंदर ही अंदर भले ही फैसला हो चुका था, लेकिन बीजेपी ने हिमंत बिस्वा सरमा को असम का मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद ही बनाया था। सिंधिया बीजेपी में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में हो या न हों, लेकिन कोई दो राय नहीं कि वो राहुल गांधी के दिमाग में नहीं होंगे और ये भी मानकर ही चलना चाहिये कि आने वाले 2023 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आदिवासी टंटया मामा की समाधी स्थल पर पुष्प अर्पित किये साथ ही संदेश दिया कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के साथ खड़ी रही हैं और आगे भी खड़ी रहेगी।

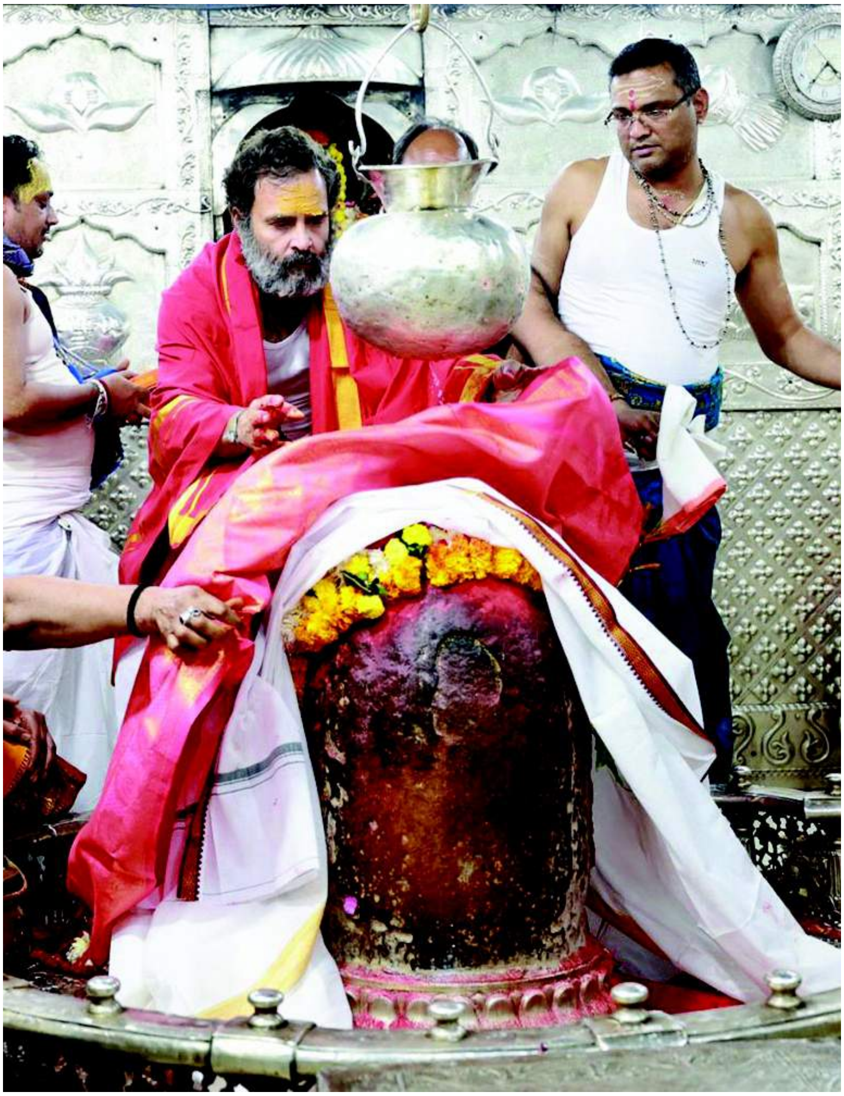

उनकी टीम के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे।

राहुल गांधी अपनी एक जिद तो पूरी ही कर चुके हैं। ये जिद भी मल्लिकार्जुन खड़गे को कमान सौंपा जाना नहीं, बल्कि राहुल गांधी का खुद कांग्रेस अध्यक्ष न बनना है। जाहिर है अगला कदम बीजेपी से बदले का ही टारगेट होगा। मध्य प्रदेश की राजनीतिक जमीन राहुल गांधी के लिए बीजेपी से बदले के काफी माकूल भी लगती है। सिंधिया को लेकर इससे पहले राहुल गांधी का कहना रहा है कि उनको अपने भविष्य की फिक्र थी और कुछ निजी चिंताएं, इसीलिए विचारधारा से समझौता करते हुए वो बीजेपी में चले गये। बाद में सिंधिया जैसे नेताओं को राहुल गांधी ने डरपोक बताया था। राहुल गांधी ने अपनी टीम को सलाह दी थी कि ऐसे लोगों को वे जाने दें और बाहर से निडर नेताओं को कांग्रेस में लाया जाना चाहिये। भले ही वे संघ और बीजेपी में ही क्यों न हों। मध्यप्रदेश में राहुल गांधी के साथ एक ऐसे नेता भी साथ साथ चलते देखे गये हैं, नाना पटोले। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पहले बीजेपी के नागपुर से सांसद हुआ करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर विरोध करने के लिए वो चर्चित रहे हैं - और ये बात ही राहुल गांधी के मन को छू जाती है। जिस तरह से परिवार और पार्टी के पूरे लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी मध्यप्रदेश में मार्च कर रहे हैं, चुनावी इरादा समझना बहुत मुश्किल नहीं लगता। चुनाव तो गुजरात में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही हुआ है, लेकिन राहुल गांधी दूर ही रहे हैं। गुजरात में तो एक दिन चुनाव प्रचार किया भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश तो झांकने तक नहीं गये। हो सकता है राहुल गांधी और उनकी कोर टिम को पहले ही लग गया हो कि गुजरात में दाल तो गलने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी चांस कम ही दिखे हों। एक वजह आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की हद से ज्यादा सक्रियता भी हो सकती है। वैसे भी गुजरात में कांग्रेस के मुकाबले अभी से ही आम आदमी पार्टी को ज्यादा मजबूत देखा जाने लगा है। मध्यप्रदेश को लेकर एक दलील तो बनती ही है। मध्यप्रदेश में तैयारी के लिए अभी पूरा वक्त भी है। करीब साल भर का समय भी बचा हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक बनाये गये दिग्विजय सिंह के फंसे होने के चलते कमलनाथ को पहले से ही

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उज्जैन महाकाल मंदिर में पूजन अर्चना की। इस दौरान मध्यप्रदेश कांग्रेस के कई नेता उनके साथ मौजूद थे।

मध्यप्रदेश पर फोकस करने को बोला जा चुका है।

ये यात्रा का चुनावी हिस्सा है

निश्चित तौर पर मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछली बार की ही तरह दिग्विजय सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन दारोमदार तो कमलनाथ पर ही होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से चले जाने और दिग्विजय सिंह के लगभग दिल्ली अटैच हो जाने के बाद कमलनाथ को तो खुला मैदान ही मिल गया है। 2020 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त कमलनाथ के एक बयान ने सत्ता के गलियारों में सबका ध्यान खींचा था, आज के बाद कल और कल के बाद परसों भी आता है। कल तो कब का बीत चुका है, राहुल गांधी की नजर अब परसों पर ही टिकी लगती है। कांग्रेस नेताओं की पूरी कोशिश लगती है कि राहुल गांधी एक बार फिर 2018 जैसा ही चमत्कार दिखा दें, तभी तो दक्षिण भारत के बाद भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा तामझाम मध्यप्रदेश की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश के मालवा-निमाड़ क्षेत्र के 6 जिलों में आने वाली 17 विधानसभाओं से गुजरी है। ये इलाका कांग्रेस के लिए खास मायने रखता है क्योंकि यहीं पर मध्यप्रदेश की 66 विधानसभा सीटें हैं और खास बात ये है कि 2018 में कांग्रेस ने आधे से भी ज्यादा 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में बीजेपी इलाके की 29 विधानसभा सीटें ही जीत पायी थी। मध्य प्रदेश में 12 दिन में 380 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गुजरात में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले 4 दिसंबर को ये यात्रा राजस्थान का रुख करेगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत अपने गढ़ में सचिन पायलट के साथ कैसे पेश आते हैं?

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों के अंत की शुरूआत

सौम्या को जेल, सकते में बघेल

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आसपास एक ऐसी चांडाल चौकड़ी बनाई, जिसने प्रदेश में दमन, अत्याचार और भ्रष्टाचार का ऐसा कुचक्र फैलाया, जिसका छत्तीसगढ़ राज्य साक्षी बना। चौकड़ी की प्रमुख सदस्य जिसे प्रदेश की सुपर सीएम की पदवी हासिल थी, सौम्या चौरसिया अब सलाखों के पीछे है। बीते 04 वर्षो से सौम्या चौरसिया ने एक नही बल्कि अनेकों शासकीय योजनाओं में गजब का भ्रष्टाचार मचाया। अगर हम यह कहे कि सौम्या ने भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा था तो इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत्रों के अनुसार सौम्या की गिरफ्तारी राज्य के मुखिया भूपेश बघेल के लिए गले का कांटा बन सकता है क्योंकि सौम्या के भ्रष्टाचार में बघेल की सहभागिता बराबर रही है। मौजूदा भूपेश बघेल सरकार ने पिछले चार साल में भ्रष्टाचार में बड़ी कामयाबी हासिल की है। निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक भ्रष्टाचारियों ने आतंक मचा रखा है। ऐसे माहौल में आज सौम्या चौरसिया की किसी को चौकाने वाली नहीं लगती है क्योंकि सब जानते थे कि एक न एक दिन ऐसा होने वाला है।

सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद यह सिलसिला यहां अब रुकने वाला नहीं। उनके चारों भाई भी ईडी की जद में आने ही वाले हैं। यह मेरे जैसे तमाम उन लोगों की जीत है, जिन्होंने सत्ता के नशे में चूर इन लोगों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज से करीब 2.5 साल पहले मैंने अपनी पत्रिका जगत विजन में पहली स्टोरी कवर की और उसके बाद अनेकों अंक, पोस्ट छत्तीसगढ़ में दमन, अत्याचार और भ्रष्टाचार जो मुख्यमंत्री और इनकी चांडाल चौकड़ी ने स्थापित किया उस पर लिखा।

राज्य के मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी, आईएएस और आईपीएस अफसर तक डिप्टी सेक्टरी रैंक की इस महिला अफसर का रॉब इतना अधिक था कि कई बार तो चौरसिया ने केबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री बघेल के सामने अफसरों को फटकार लगा दी। यही नहीं सौम्या चौरसिया के भ्रष्टाचार की परतें जब पत्रकार सुनील नामदेव ने खोलना शुरू की तो इस क्रूर अफसर महिला ने सुनील

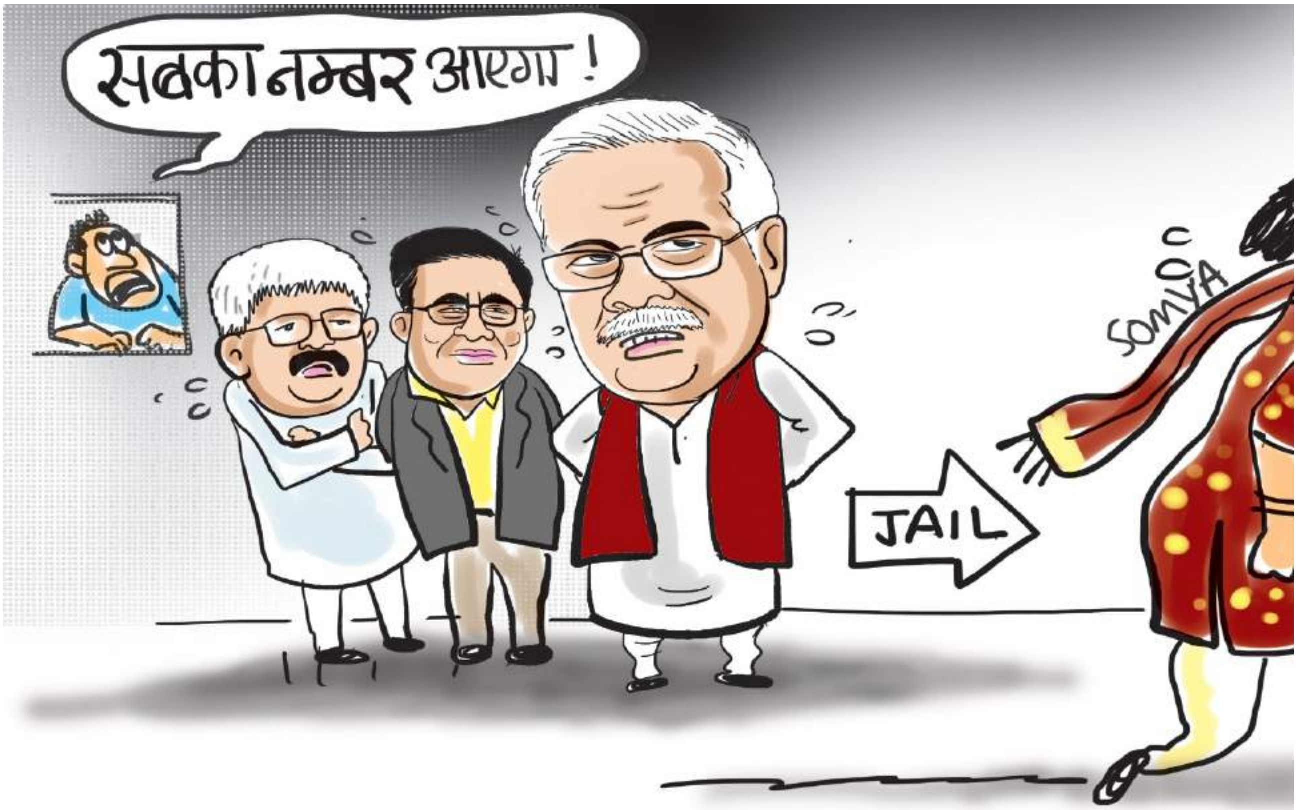

नामदेव का घर तुड़वा दिया, उन्हें जेल भेज दिया और उन्हें सैनेटाइजर पिलाने तक की कोशिश की। अभी यह मामला यहां रुकता खत्म नहीं होता दिख रहा। ईडी के उच्च सूत्रों के अनुसार अब ईडी की नज़र में शराब और अन्य कमाई भी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री सरकारी स्तर पर होती है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत अवैध अर्थात बिना टैक्स वाली शराब बिकती है। सूत्रों के मुताबिक इसका पूरा जिम्मा चांडाल चौकड़ी की दूसरी गैंग संभालती थी, जिसे नान घोटाले का मुख्य आरोपी और महापौर का भाई संभालते हैं। अब प्रदेश की पूरी ऊगाही इन्हीं के कंधे के ऊपर आ गई है। ईडी की नज़र अब अनिल टुटेजा और ढ़ेबर पर है। केन्द्र तक यह जानकारी भी पहुंच चुकी है, कि सुप्रीम कोर्ट की हर पेशी पर 50 लाख से ऊपर पैसा खर्चा करके टुटेजा अभयदान प्राप्त कर रहे है। चांडाल चौकड़ी के यह सदस्य भी जल्द जेल में दिखाई देंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री परिवार से भी किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। केंद्र अब छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग पर भी कार्यवाहियां की तैयारी कर रहा है, जिसमें जनसंपर्क आयुक्त के साथ-साथ प्रदेश के एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी और राज्य सेवा से आए पुलिस अधिकारियों की कुंडली तैयार की जा रही है। इसमें इनके द्वारा ऑनलाइन ऐप, जमीन मामले और सौम्या चौरसिया के कहने पर दमन प्रमुख है। इसके साथ ही प्रदेश एक महापौर और उनके भाई पर भी गोपनीय जांच चालू हो गई है और आगे इनका भी नंबर आयेगा। छत्तीसगढ़ में लूट खसोट का ऐसा दुश्चक्र चला की हर कोई प्रदेश की जनता का पैसा लूटने में लग गया। कोयला, लौह, शराब, जमीन, ठेके आदि में बे-हिसाब पैसा कमाया गया। आज हालत यह है कि चौकड़ी का एक सदस्य अभी अंदर गई है, अनिल टुटेजा कहीं छिप गए हैं, विनोद वर्मा के सुप्रीम कोर्ट केस में अचानक तेजी आई हुई है बल्कि आशंका यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं की गिरफ्तारी ही ना हो जाए। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ अशांत रहने वाला है।

वैसे भी भूपेश बघेल के आगे की राजनीतिक यात्रा ठीक नहीं दिख रही आरक्षण मामले में आदिवासी इनके खिलाफ हो गए हैं। अभी विधानसभा में पारित आरक्षण से प्रदेश के सतनामी समाज नाराज हो गया है। गरीब सवर्ण भी सरकार से नाराज है। ऐसे में 2023 में पिछड़ा समाज और छत्तीसगढ़ी नैरेटिव से चुनाव जीता नहीं जा सकता है। आशंका तो यह है कि चुनाव तक भूपेश स्वयं ही गिरफ्तार ना हो जाए।

गुजरात विधानसभा चुनाव...

आदिवासियों पर मोदी, केजरीवाल और कांग्रेस की नजर

समता पाठक

गुजरात चुनाव चरम पर है। चुना प्रचार भी जमकर हो रहा है। सभी पार्टियां अपने-अपने वादे कर रही है। गुजरात चुनाव में आदिवासी वोटर को लुभाने का सिलसिला तो काफी पहले से चल रहा है, अब तो रेस ज्यादा ही तेज हो चली है। गुजरात का आदिवासी वोटर हार जीत का फैसला तो नहीं कर सकता, लेकिन चुनावों जिसके साथ हो जाये ताकतवर बना सकता है। देखना है 90 के दशक से पहले आदिवासी वोटर पर सिर्फ कांग्रेस का असर हुआ करता था, लेकिन फिर बीजेपी ने सेंध लगा दी और अब ये काम करने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा की 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और माना जाता है कि करीब करीब इतनी ही अन्य सीटों पर भी आदिवासी वोटर का ही प्रभाव है। 2017 में आरक्षित सीटों में सबसे ज्यादा 15 सीटें जीती थी। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने 08 सीटें और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी की दोनों सीटें आदिवासी इलाके से ही मिली थीं। गुजरात के 15 फीसदी आदिवासी वोट बैंक के लिए कांग्रेस तो अपने आदिवासी नेताओं की

अपने समुदाय में पैठ के भरोसे चल रही है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल जहां आदिवासी संकल्प सम्मेलन के जरिये इलाके में पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात आदिवासी गौरव यात्रा के जरिये आदिवासी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

बीजेपी को भी लगने लगा है कि बगैर आदिवासी समुदाय के सपोर्ट मिले, वैतरणी पार होना मुश्किल है। पिछले चुनाव में अगर आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की जगह बीजेपी को वोट मिल गये होते तो कड़े संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती, लिहाजा बीजेपी ने इस बार पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने माना भी कि असल मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के ब्रह्मास्त्र हैं क्योंकि चुनावों में उनका चेहरा बीजेपी को हर तरह से फायदा पहुंचाता है। सीआर पाटिल तो यहां तक कहते हैं, अगर हम गलती भी करते हैं तो मोदी की वजह से लोग हमें माफ कर देते हैं। नाराज होते हुए भी वो हमे माफ कर देते हैं। ये एक प्लस प्वाइंट है। मोदी की लोकप्रियता ऐसी है कि जनता उनके हाथ मजबूत करने के लिए भी बीजेपी को वोट दे देती है। जो माहौल बना हुआ है। गुजरात का आदिवासी वोटर ये तो समझ चुका है कि हर राजनीतिक दल का ज्यादा जोर उसे रिझाने और फिर वोट हासिल करने पर है, लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी समुदाय पर असर किसका ज्यादा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अरविंद

केजरीवाल का या फिर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का?

आदिवासी फ्रंट पर मोदी ने मोर्चा संभाला

ये तो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही मालूम हो गया था कि आने वाले चुनावों में बीजेपी की नजर आदिवासी वोटों पर है। ये क्रेडिट तो बीजेपी ले ही चुकी है कि पहली बार किसी आदिवासी नेता तो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने में मददगार बनी है।वैसे भी एडवांस में किये गये ऐसे उपाय चुनावी मौसम में फसल काटने के लिए ही तो होते हैं। ये भी संयोग ही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हाल फिलहाल आदिवासी इलाकों में दौरे का कार्यक्रम भी बना हुआ है और जाहिर है बीजेपी ऐसे मौके का फायदा उठाने में तो कोई भी चूक करने से रही। गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात आदिवासी गौरव यात्रा निकाल कर आदिवासी वोटर को ही तो साधने की

कोशिश कर रहे हैं।

रिझाने की कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, देखना है आदिवासियों का रुझान किस तरफ है?

दक्षिण गुजरात में जब तक आदिवासियों का अच्छा समर्थन नहीं मिला, बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी के लिए पांच साल पहले जैसा ही संघर्ष करना पड़ सकता है। तभी तो बीजेपी की भारी भरकम टीम को आदिवासी इलाके के मोर्चे पर पहले से ही झोंक दिया गया है। टीम में केंद्रीय मंत्री, सांसद और गुजरात सरकार के मंत्री और विधायक घूम घूम कर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने आदिवासी समुदाय को ऐतिहासिक गौरव दिलायी है। साथ ही, आदिवासी लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिल कर काम कर रहे हैं। मतलब बहाने से डबल इंजिन सरकार की अहमियत भी समझायी जा रही है।

दक्षिण गुजरात में जब तक आदिवासियों का अच्छा समर्थन नहीं मिला, बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी के लिए पांच साल पहले जैसा ही संघर्ष करना पड़ सकता है। तभी तो बीजेपी की भारी भरकम टीम को आदिवासी इलाके के मोर्चे पर पहले से ही झोंक दिया गया है।

बीजेपी को एक दिक्कत जरूर हो रही है क्योंकि आदिवासी समुदाय अपने समुदाय के नेता की राजनीतिक भाषा ही ठीक से समझ पाता है। कांग्रेस के पास अनंत पटेल एक ऐसे ही नेता हैं, बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को चारों तरफ से घेरने की है और प्रधानमंत्री मोदी का शुरू से ही इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर नजर आता है। जैसे ही आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, कांग्रेस ही उनके निशाने पर होती है। घुसपैठ तो अरविंद केजरीवाल की भी महसूस की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का नाम लेकर हो सकता है मोदी अपनी तरफ से केजरीवाल को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हों। चुनावों में बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी तो अक्सर ही देखने को मिलती रही है। प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी लोगों से कनेक्ट होने के प्रयास में कहते हैं, एक तरह कांग्रेस की तो दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार देख लीजिये। कांग्रेस के नेताओं ने आदिवासी समाज का सिर्फ मजाक उड़ाया। पहले की सरकार को आपकी नहीं, आपके वोट की चिंता हुआ करती थी। वैसे मोदी की ये बात आदिवासी समुदाय को थोड़ा कन्फ्यूज भी

कर सकती है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी पहले वाली किसकी सरकार की बात कर रहे हैं? अगर वो गुजरात की कांग्रेस सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो तो 27 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। और अगर वो केंद्र की कांग्रेस सरकार की नीतियों की याद दिलाना चाहते हैं, तो भी दोबारा सत्ता में आने के बाद पिछली सरकारों को दोष देने का क्या मतलब रह जाता है? ये तो बिहार में साल दर साल होने वाली हर चुनावी रैली में लालू-राबड़ी शासन को जंगलराज और माफी मांग चुके नयी पीढ़ी के नेता तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज बताने जैसा ही है।

बीजेपी सरकार के काम गिनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, वलसाड में खूब बारिश होती है, लेकिन सारा पानी बह जाता था। कांग्रेस नेताओं ने उसके लिए भी कभी कोई काम नहीं किया। भाजपा ने वे सारे काम किये जिससे ऊकाई डैम योजना का लाभ आदिवासी लोगों को मिल सके। मोदी की लोकप्रियता भुनाने की बीजेपी चाहे जैसे और जितनी भी कोशिश करे, लेकिन ये काम तो 2017 में भी हुआ ही था। गुजरात में तो कांग्रेस से संघर्ष में कड़ा मुकाबला तो करना ही पड़ा, आदिवासी इलाकों में तो कांग्रेस के आगे बीजेपी की दाल नहीं ही गल पायी। क्या इस बार आदिवासी लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को कोई खास असर होने जा रहा है?

बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला

बीजेपी नेतृत्व के लिए आदिवासी इलाकों में पैठ बनाने में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस के युवा विधायक अनंत पटेल हैं, जो दीवार बन कर खड़े हो जा रहे हैं। अनंत पटेल दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले की वंसदा सीट से विधायक हैं और विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से विपक्ष की सबसे ज्यादा मजबूत विरोध की आवाजों में से एक माने जाते हैं। अनंत पटेल की ताकत का अंदाजा समझने के लिए एक ही वाकया काफी है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने पार, तापी और नर्मदा नदियों को जोड़ने की एक परियोजना का इसी साल बजट में प्रावधान किया गया था, लेकिन अनंत पटेल ने ऐसा आंदोलन चलाया कि बीजेपी करीब करीब वैसी ही हिली हुई नजर आयी जैसा कि किसानों के दबाव में कृषि कानूनों को लेकर देखा गया था। कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने ये कह कर विरोध शुरू कर दिया कि प्रोजेक्ट के जरिये हमारी जमीनें छीन ली जाएंगे। हम अपने घरों और खेतों से बाहर हो जाएंगे। हम कंक्रीट के जंगलों में नहीं बल्कि कुदरती जंगलों में ही रहना चाहते हैं। अनंत पटेल ने विरोध के लिए जागरुकता अभियान चला दिया और देखते ही देखते पूरे इलाके में बैठकें होने लगीं जिनमें महिलाओं और बच्चों के साथ लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। जब विरोध के स्वर गांधीनगर तक पहुंचने लगे तो गुजरात बीजेपी के नेता हद से ज्यादा परेशान होने लगे। थक हार कर गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को केंद्र सरकार से परियोजना वापस लेने की सिफारिश करनी पड़ी। हाल तो परियोजना का भी कृषि कानूनों का ही हुआ, बस ये बात किसी ने नहीं कही कि तपस्या में ही कोई कभी रह गयी होगी। महीना भर पहले की ही बात है, जब अनंत पटेल पर हुए हमले के का मामला भी काफी तूल पकड़ लिया था। तब अनंत पटेल का कहना रहा कि जब वो नवसारी में एक सभा के लिए जा रहे थे तभी कुछ लोगों ने उनको पीटा और कार में तोड़ फोड़ की। अनंत पटेल के मुताबिक, हमलावर कह रहे थे कि वो आदिवासियों के नेता बन रहे हैं इसलिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी

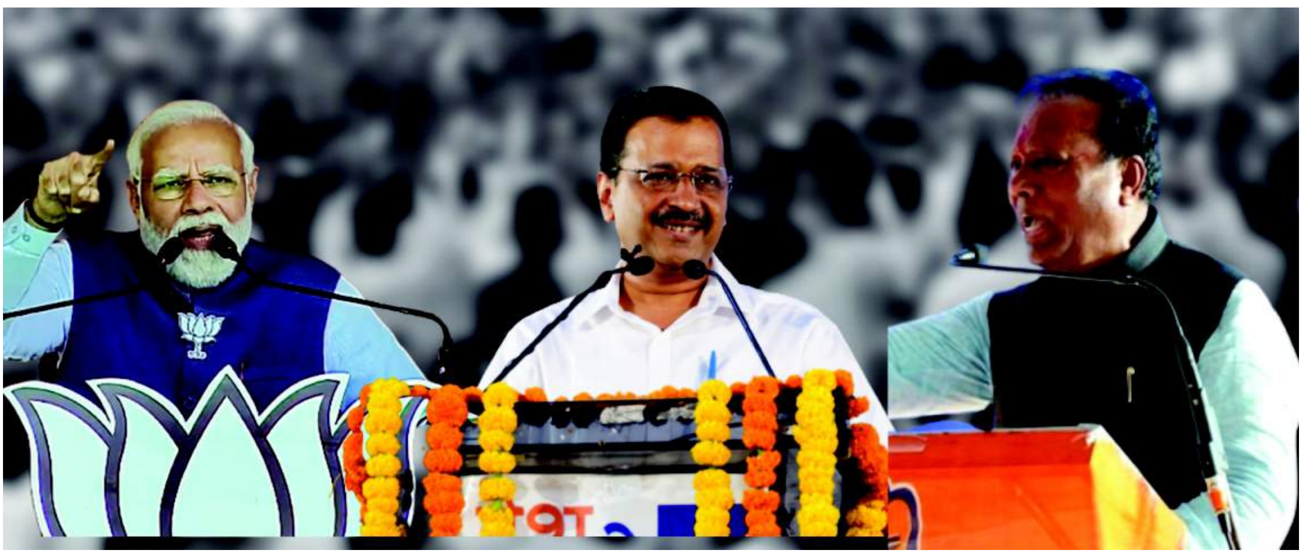

आदिवासी को यहां नहीं चलने देंगे। अनंत पटेल पर हमले के खिलाफ तो समर्थकों ने इलाके में कोहराम ही मचा दिया था। विरोध में भीड़ जमा हो गयी और एक दुकान में आग लगाने के साथ ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर डाली थी। आदिवासियों के लिए लड़ने वाले अनंत पटेल पर हुआ हमला भी बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

गुजरात में राहुल गांधीः हिमाचल प्रदेश चुनाव से पूरी तरह दूर रहे राहुल गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए गए। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए गए। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे उपचुनावों के साथ ही 8 दिसंबर को आने की अपेक्षा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के तमाम नेता हिमाचल प्रदेश में खासे एक्टिव देखे गये, लेकिन गुजरात में कांग्रेस स्थानीय नेताओं पर इस बार ज्यादा भरोसा कर रही लगती है। दिल्ली से सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत सहित करीबी नेताओं की टीम जरूर लगा रखी है।

केजरीवाल अलग ही अंगड़ाई ले रहे हैं

अव्वल तो अरविंद केजरीवाल से परेशान कांग्रेस को होना चाहिये, लेकिन बीजेपी ज्यादा ही चिंतित लग रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी भले ही केजरीवाल और उनकी पार्टी को इग्नोर कर रहे हों, लेकिन वो तो बीजेपी के खिलाफ ही हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। आदिवासी संकल्प सम्मेलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर 27 साल में गुजरात को बदहाल कर देने का आरोप लगाया और दोहराया कि गुजरात में सरकार बनने की सूरत में वो दिल्ली और पंजाब जैसा गवर्नेंस मॉडल लागू करेंगे। पहले भी अरविंद केजरीवाल कई चीजों की गारंटी दे चुके हैं, लेकिन ये सब तो तब लोगों को समझ में आएगा जब किसी को लगे कि आम आदमी पार्टी भी गुजरात में सत्ता की बराबर की दावेदार है। फिर भी वचनं किम् दरिद्रम् वाले अंदाज में अरविंद केजरीवाल समझाते हैं, गुजरात में एक करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। देश के सबसे अमीर दो आदमी और सबसे गरीब आदिवासी - दोनों गुजरात से ही हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी वाले अंदाज में ही बीजेपी और लीडरशिप को जी भर खरी खोटी सुनाने हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा में आदिवासी समाज के लिए कुछ योजनाओं की गारंटी का ऐलान किया था, जिसमें फ्री बिजली और बेरोजगारों को नौकरी देने की गारंटी की बात कही गयी थी। साथ ही, आदिवासियों के हर इलाके में स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, अस्पताल, सड़क और बेघर आदिवासियों के लिए आवास की गारंटी दी थी और आदिवासियों के लिए पेसा कानून लागू करने के वादे के साथ ही ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन भी आदिवासी समुदाय से ही बनाने का वादा कर रखा है। देखा जाये तो गुजरात के आदिवासी समुदाय के बीच अनंत पटेल के माध्यम से राहुल गांधी, खुद अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अपने तरीके से रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब देखना है कि आदिवासी लोग सुनते किसकी बात हैं?

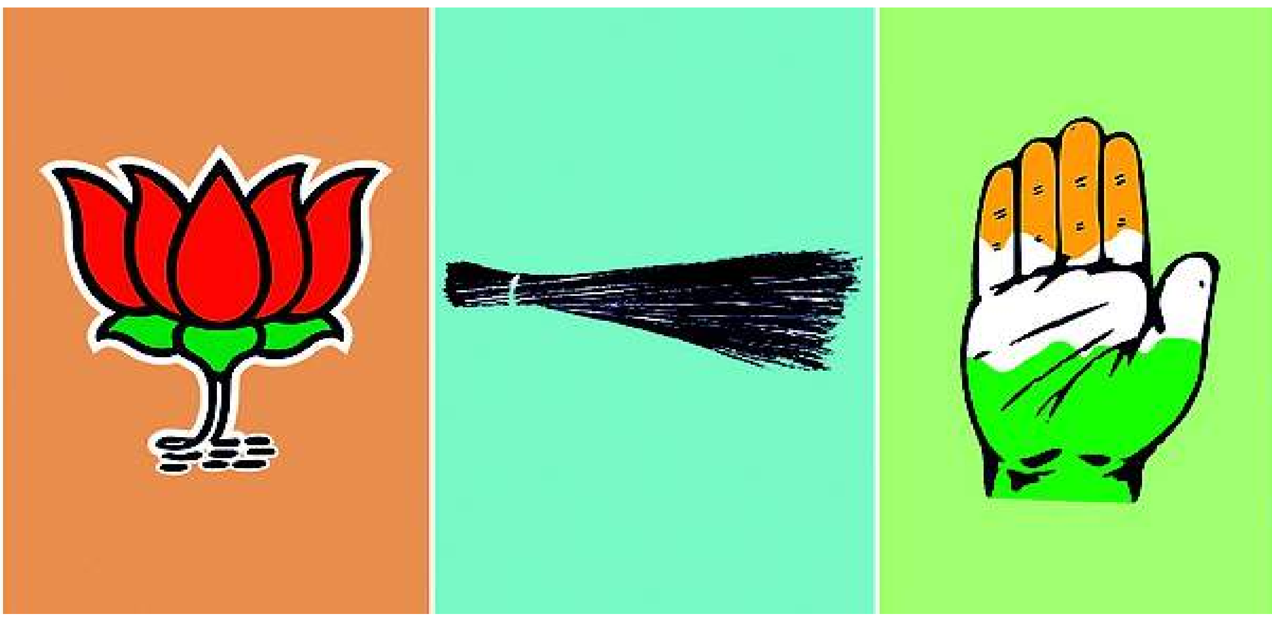

सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कांग्रेस मंजधार में

प्रियंका पटनायक

सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान यानी गांधी परिवार पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ऐलान कर चुके हैं कि वो सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे। राजस्थान कमान के लिए दोधारी तलवार बन गया है। जिस पर कांग्रेस चलना नामुमकिन होता जा रहा है। राजस्थान के प्रभारी पद से अजय माकन के इस्तीफा के बाद कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन गहलोत के बीच चल रहा विवाद इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। क्योंकि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न अजय माकन की गहलोत गुट के 03 बागियों पर कार्रवाई करने की बात पर ध्यान दिया। और न ही कांग्रेस आलाकमान यानी गांधी परिवार के करीबी सचिन गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर की जा रही मांगों पर कुछ कहा है। इस बीच खबर है कि हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले इसे लेकर हुई एक बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने शिरकत की। लेकिन, दोनों नेताओं में बातचीत छोड़िए, दुआ-सलाम तक नहीं हुई। दरअसल, कांग्रेस आलाकमान के लिए राजस्थान एक विकट समस्या बनता जा रहा है और, कांग्रेस दो पाटों के बीच पिसती नजर आ रही है। और ऐसा लगता है कि सचिन पायलट का दबाव कहीं कांग्रेस का गुब्बारा ही न फोड़ दे। सचिन पायलट गुर्जर नेता हैं। और राजस्थान में लंबे समय से गुर्जर सीएम की मांग की जा रही है।

गुर्जर नेता के जरिये पायलट की राहुल गांधी को चुनौती

राजस्थान में गुर्जर आबादी करीब 06 प्रतिशत है और गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव करीब 40 सीटों पर है। यही कारण है कि गुर्जर नेता विजय सिंह बैंसला ने सीधे राहुल

गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी दे दी। विजय सिंह बैंसला ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार का एक साल बचा है। अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो आपका (राहुल गांधी) स्वागत है, नहीं तो हम विरोध करेंगे। हमने गुर्जर मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए वोट दिया था। हमारे कुछ समझौते हुए थे। जिन पर काम नहीं हो रहा है। दरअसल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंचने वाली है। और इससे पहले गुर्जर नेता का विरोध कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्योंकि, राजस्थान में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगर गुर्जर मतदाता कांग्रेस के पाले से खिसक जाएगा। कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने की संभावना बन जाएगी। वैसे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में अधिकांश रूट गुर्जर मतदाताओं के प्रभाव वाली विधानसभा सीटों से गुजरेगा। तो, शक्ति प्रदर्शन करने में सचिन पायलट शायद ही कोई कोताही बरतेंगे। आसान शब्दों में कहें, तो सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और अब तो पायलट गुट के साथ ही गहलोत गुट के भी कुछ विधायक मुखरता और दबी आवाज में सचिन के पक्ष में होने की आवाज उठाने लगे हैं। वैसे सचिन पायलट भी माहौल को गर्म रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय दिख रहे हैं। और गहलोत गुट पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते रहते हैं। वैसे संभावना जताई जा सकती है कि भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के साथ ही राजस्थान को लेकर फैसला आ सकता है। क्योंकि तब तक गुजरात के कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत को संभवतया हार का जिम्मेदार घोषित किया जा सकता है। जिसके बाद सचिन पायलट की राह आसान हो सकती है। लेकिन, इसमें भी कुछ अड़चने हैं।

कांग्रेस आलाकमान के आगे कुआं और पीछे खाई

राजस्थान के सियासी संकट को खत्म करने के लिए ही कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उम्मीदवार बनाया जाना तय हुआ था। और इसी वजह से राजस्थान के तत्कालीन प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाकर सूबे में भेजा गया था। लेकिन, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की आशंका के चलते गहलोत गुट के विधायकों ने बगावत कर दी। हालांकि, बाद में अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांगी। और ये माफी शायद कबूल हो गई। क्योंकि न अशोक गहलोत की कुर्सी पर कोई खतरा नजर आया और न ही बगावत पर नोटिस पाने वाले 3 करीबियों पर कोई कार्रवाई हुई। जिसके बाद गुजरात के प्रभारी के तौर पर अशोक गहलोत एक्टिव हो गए। इतना ही नहीं गहलोत ने नोटिस पाए विधायकों को ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारियां भी सौंप दीं। कांग्रेस आलाकमान के सामने असल समस्या ये है कि अगर वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश करता है। तो राजस्थान में गहलोत गुट के विधायक बगावत कर देंगे। संभव है कि पार्टी टूटने तक की नौबत आ जाए। वहीं सचिन पायलट की मांगें न मानने पर भी कांग्रेस सरकार पर खतरा बना ही रहेगा। क्योंकि पायलट के नेतृत्व में पहले ही एक बार बगावत हो चुकी है और अगर सचिन पायलट की मांगों को लगातार दरकिनार किया गया तो संभव है कि वह भी हिमंत बिस्वा सरमा की राह पर चल पड़ें। क्योंकि राजस्थान में भाजपा के साथ जाने पर उनके पास मुख्यमंत्री बनने का मौका रहेगा जो कांग्रेस में रहते फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। आसान शब्दों में कहें तो अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति बनी हुई है।

दिल्ली के एमसीडी चुनाव...

क्या केजरीवाल कामयाब हो सकते हैं?

नीरज दिवाकर

अरविंद केजरीवाल अभी एक साथ दो नावों पर सवार होना पड़ रहा है। एमसीडी चुनाव की तैयारी तो वो पहले से भी कर ही रहे होंगे, लेकिन सोचा नहीं होगा कि ये चुनौती भी तभी आ खड़ी होगी जब वो गुजरात विधानसभा चुनावों में व्यस्त रहे होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव अगर अरविंद केजरीवाल की चढ़ती राजनीति की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हिस्सा है तो एमसीडी चुनाव नींव का एक भाग - लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इमारत की अलग अलग दीवारें जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में वो नींव को ही दुरूस्त करने से चूक जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बाकियों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल खुद भी एक सवाल से जूझ ही रहे होंगे कि दिल्ली विधानसभा से बाहर की चुनावी राजनीति में वो हर बार फेल क्यों हो जाते हैं। एमसीडी चुनाव में कुछ खास तो नहीं ही कर पाते, आम चुनाव में तो कांग्रेस भी पछाड़ देती है और कई सीटों पर तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाती है। शुरुआत तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में ही हो चुकी थी, नतीजे आने के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने हनुमान जी थैंक यू बोला तो और आगे बढ़ने की हिम्मत हुई और दिवाली आते आते टीवी पर विज्ञापन देकर जय श्रीराम के नारे लगाने लगे। यूपी विधानसभा चुनाव का वक्त आने पर अयोध्या तक पहुंच गये थे। अब जय श्रीराम बोलने का असर ये हुआ है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाने की बात करने लगे हैं। मतलब, एमसीडी में आप को बहुमत में लाने से है।

मगर, मुश्किलों ने चारों तरफ से ऐसे घेर रखा है कि हर कदम पर जूझना पड़ रहा है सत्येंद्र जैन की जेल की ऐश जो फजीहत करा रही है, वो तो अलग ही है।

आप की डबल इंजन सरकार ?

एमसीडी चुनावों को ही ध्यान में रख कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कूड़े के ढेर को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तिहाड़ जेल से एक एक करके सामने आये सीसीटीवी फुटेज ने ऐसी फजीहत शुरू करायी कि जवाब देते नहीं बन रहा है फिर भी राजनीति में नये पैंतरे

नगर निगम दिल्ली

खोज लेना अरविंद केजरीवाल के लिए कोई कठिन काम तो है नहीं।

अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में कुछ भी पा लिया, गुजरात जैसी ही उपलब्धि समझी जाएगी।

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल में मसाज कराते वीडियो क्लिप आने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपने तरीके से बचाव जरूर किया था। मेडिकल ग्राउंड पर फुट मसाज को फीजियोथेरेपी के तौर पर समझाने की कोशिश की। आप नेता गोपाल राय तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जेल के दिनों की याद दिलाने लगे लेकिन सत्येंद्र जैन ने कोई मामूली रायता तो फैलाया नहीं है। अब तो खाने पीने से लेकर तमाम इंतजामों के फुटेज यही बता रहे हैं कि जेल की सजा सबके लिए नहीं होती।

आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आमने सामने की तकरार तो तभी से चल रही है जब से सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की है और मुसीबत वाले मौके को टिवस्ट देते हुए आप नेताओं ने 2024 में मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल शुरू करा दिया।

अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों बीजेपी के डबल इंजन की सरकार का नारा भी हथियाने का प्रयास किया है। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद मोदी ने अरविंद केजरीवाल के चुनाव निशान को स्वच्छता अभियान से जोड़ कर पूरे देश में झाड़ू लगवा दिया था। अब कौन किसके सामान को झटक कर क्या और कितना हासिल कर सकता है, बात अलग है।

बीजेपी तो हर विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार की बात करती है और लोगों को उसके तमाम फायदे समझाये जाते हैं। बीजेपी ने तो दिल्ली चुनाव के ठीक बाद बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बनवायी थी, लेकिन नीतीश कुमार तो इंजन ही ले उड़े और ट्रैक बदलने के बाद लालू यादव के डिब्बे जोड़ दिये।

एमसीडी चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव में आम आदमी पार्टी नये स्लोगन के

साथ आयी है और कैंपेन थीम बीजेपी की पूरी तरह कॉपी लग रही है। पहले चरण में आप ने एमसीडी में भी केजरीवाल के थीम पर सभी उम्मीदवारों की पदयात्रा, जनसंवाद और डोर टू डोर कैंपेन चलाया था। आप नेताओं ने दिल्ली के लोगों को कैंपेन के दौरान ये समझाने की कोशिश की कि अगर पार्टी को एमसीडी में बहुमत मिली तो सारे काम बिलकुल वैसे ही होंगे जैसे दिल्ली सरकार में हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की टीम जगह जगह पहुंच कर बता रही थी कि जिस तरह दिल्ली के लोगों के लिए बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, यात्रा, तीर्थ यात्रा और तमाम इंतजाम और सुविधायें मुहैया करायी जा रही हैं, एमसीडी में भी पार्टी के सत्ता में आ जाने के बाद ऐसी सुविधाओं को और विस्तार मिलेगा।

और अब चुनाव कैंपेन के दूसरे फेज में नया स्लोगन लाया गया है - केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद।

नयी थीम के एक हजार नुक्कड़ सभा, डांस फॉर डेमोक्रेसी, नुक्कड़ नाटक, गिटार शो, मैजिक शो और बज-एक्टिविटीज के जरिये चुनाव प्रचार 23 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये सिलसिला अब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 02 दिसंबर तक चलता रहेगा। दिल्ली में एमसीडी के लिए वोटिंग 04 दिसंबर को होनी है। नतीजे हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उपचुनावों के साथ ही आएंगे। आम आदमी पार्टी का नया पूरी तरह बीजेपी के डबल इंजन सरकार कैंपेन की कॉपी है और खुद मनीष सिसोदिया इसे कंफर्म भी कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं, ये अभियान स्पष्ट तौर पर बीजेपी के डबल इंजन सरकार के चुनावी नारे का जवाब है। बीजेपी नेता अपनी डबल इंजन सरकार के कैंपेन में दावा करते हैं कि अगर केंद्र और राज्य दोनों ही जगह उनकी पार्टी की सरकार होगी तो विकास के काम भी दुगुनी गति से होंगे। ये समझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता अमित शाह बार बार इल्जाम लगाते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं को लटका दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर तो ये देखा भी गया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू शुरू में काफी अड़ंगे लगाने की कोशिश की थी। दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर मनीष सिसोदिया कहते हैं, दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी थी। स्कूल, सड़क, अस्पताल केजरीवाल जी ने बहुत दिये, लेकिन बीजेपी को जब नगर निगम चलाने का मौका दिया तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 15 साल में जनता बीजेपी का एक काम नहीं गिनवा पा रही। बीजेपी भी नहीं गिनवा पा रही। बीजेपी को कठघरे में खड़ा करते हुए मनीष सिसोदिया इल्जाम लगाते हैं, ये कोई अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे। केवल केजरीवाल जी को जानकारी गाली देकर वोट मांगते हैं। सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं।

केजरीवाल बार बार क्यों चूक जाते हैं?

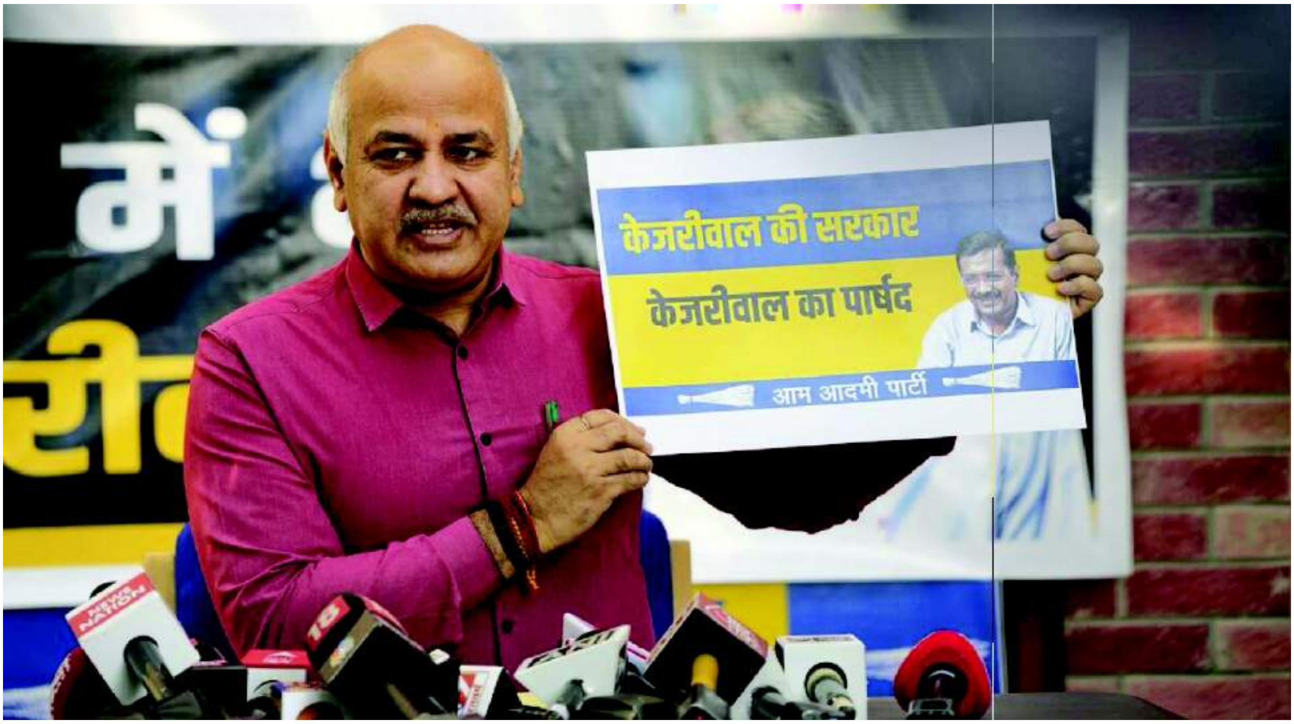

फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता काफी उग्र हो गये थे और तोड़ फोड़ भी कर डाली थी। दिल्ली में देखा जाये तो अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने की हैट्रिक लगा चुके हैं। पहली बार 2013 में, फिर 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद। पहली सरकार तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा कर कांग्रेस के सपोर्ट से ही बनायी थी, लेकिन 2015 और 2020 के चुनाव में बंपर जीत हासिल की थी। 2015 में 70 में से 67 विधानसभा सीटें और 2020 में 62 सीटें। अरविंद केजरीवाल ने 2014 और 2019 के आम चुनाव में काफी कोशिश की, लेकिन दिल्ली की सातों सीटें दोनों बार बीजेपी के खाते में आसानी से ट्रांसफर हो गये। 2014 में तो खैर वो खुद भी वाराणसी लोक सभा सीट से मैदान में थे, लेकिन कामयाबी भी मिली तो पंजाब से। तब पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित आप के चार सांसद लोक सभा पहुंचे थे। 2019 के आम चुनाव में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन तब तक शीला दीक्षित को दिल्ली कांग्रेस का कामकाज सौंप दिया गया था और वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार ही नहीं हुईं। अव्वल तो शीला दीक्षित ताउम्र नहीं भूल पायी होंगी कि कैसे एक नये नवेले नेता ने उनके इलाके में जाकर चुनावी शिकस्त दे डाली, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन के लिए मना करने के पीछे उनकी अलग दलील थी। शीला दीक्षित का कहना था कि गठबंधन के बाद कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चुनाव नतीजे आये तो मालूम हुआ कि कांग्रेस ने दिल्ली की सात में से किसी भी सीट पर अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवारों को तीसरे स्थान से ऊपर नहीं उठने दिया था और कई जगह तो वे जमानत तक नहीं बचा पाये थे। लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर लिया गया शीला दीक्षित फैसला सही साबित हुआ। 2017 के एमसीडी चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने कोई कम मेहनत नहीं की थी। वो भी कांग्रेस और बीजेपी को मायावती की ही तरह लोगों को फर्क समझा रहे थे। जैसे कह रहे हों, एक नागनाथ है तो दूसरा सांप नाथ। हद तो तब हो गयी जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से कहने लगे, बीजेपी को वोट देने से अगर उनके बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं तो उसके जिम्मेदार भी वे खुद ही होंगे।

निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये रहस्य समझ पाना मुश्किल ही हो रहा होगा। विधानसभा में तो दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को जैसे एकछत्र राज सौंप देते हैं, लेकिन लोक सभा चुनावों में उनकी दाल तक गलने नहीं देते। बीजेपी के बाद कांग्रेस को वोट दे डालते हैं और वो भी आम आदमी पार्टी को पछाड़ देती है और हद तो तब हो जाती है जब एमसीडी चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को मन मसोस कर रह जाना पड़ता है।

उत्तरप्रदेश उपचुनाव

मैनपुरी में अखिलेश यादव की दांव पर लगी साख

सपा को संजीवनी मिलने की उम्मीद

वेदकुमार

समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी उपचुनाव में ब्रह्मास्त्र उतार दिया है। कागजों में नाम तो डिंपल यादव का होगा, लेकिन हकीकत में लड़ाई अखिलेश यादव ही लड़ने जा रहे हैं। नतीजा 2024 ही नहीं, यूपी में समाजवाद का भविष्य भी तय करेगा। देर से ही सही, डिंपल यादव को आखिरकार चुनाव मैदान में उतार ही दिया गया। अब ये दुरूस्त भी है या नहीं, ये जानने के लिए चुनाव नतीजों का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। डिंपल यादव की चुनावी राजनीति की शुरुआत ऐसी ही परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन पहला अनुभव बहुत बुरा रहा और अखिलेश यादव के लिए वो किसी सदमे से कम नहीं था। आजमगढ़ उपचुनाव में भी आखिर तक डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की काफी चर्चा रही, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया। तब समझा गया कि वो डिंपल यादव को राज्यसभा भेजने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन वहां भी समाजवादी पार्टी के कोटे से आरएलडी नेता जयंत चौधरी को भेज कर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी नेताओं को एक और सरप्राइज दे डाला। अखिलेश यादव को आजमगढ़ की अपनी सीट तो गंवानी ही पड़ी थी, आजम खान की रामपुर लोकसभा सीट से भी हाथ धोना पड़ा था। अब उसी रामपुर की विधानसभा

सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। साथ ही, यूपी में एक और विधानसभा सीट खतौली में भी उपचुनाव होना है। ये तो ऐसा लगता है जैसे अखिलेश यादव के सामने यूपी चुनाव 2022 जैसी ही चुनौती फिर से खड़ी हो गयी हो।

आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है और वहां से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि मैनपुरी की ही करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव फिलहाल विधायक हैं और डिंपल यादव के लिए राहत देने वाली बस इतनी ही बात है। बीजेपी की तो 2014 से ही यूपी की ऐसी सीटों पर नजर रही जिन पर बड़े राजनीतिक विरोधी काबिज हुआ करते थे। 2019 में बीजेपी ने अमेठी हथिया लिया और 2022 में आजमगढ़ और रामपुर। बीजेपी का अगला निशाना मैनपुरी ही है। अखिलेश यादव जहां मैनपुरी के लिए डिंपल यादव का नाम उम्मीदवार के रूप में घोषित कर चुके हैं, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कोई संकेत भी नहीं दिया गया है। कयास लगाये जाने की बात और है। कहने को तो लोग मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की दो बहुओं के बीच जंग की संभावना भी जताने लगे हैं। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह की दूसरी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ ट्रंप कार्ड समझ रही हो, लेकिन मैनपुरी की लड़ाई बीजेपी के लिए आजमगढ़ जैसी आसान तो नहीं होगी। भले ही मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की ही तरह आजमगढ़ उपचुनाव में भी बीजेपी की मददगार की भूमिका में देखी गयी हों, लेकिन मैनपुरी में भी वो बिलकुल वैसा ही करेंगी, ऐसा तो नहीं लगता। बाकी सीटों पर जो भी गुणा गणित किया हो, लेकिन करहल विधानसभा सीट पर मायावती ने अखिलेश यादव की राह में कोई रोड़ा नहीं अटकाया था। उम्मीदवार उतारने के नाम पर सिर्फ रस्मअदायगी की थी। कांग्रेस ने तो वो भी नहीं किया था।

मायावती को ये भी मालूम है कि 2019 में कन्नौज सीट पर डिंपल यादव की हार के लिए अखिलेश यादव कहीं न कहीं मायावती को ही जिम्मेदार मानते हैं। ये ठीक है कि मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती मैनपुरी तक वोट मांगने गयी थीं, लेकिन अखिलेश यादव के मन में ये रहता है कि समाजवादी पार्टी को बीएसपी के वोट ट्रांसफर नहीं हो पाये, वरना कन्नौज को भी तो मुलायम सिंह परिवार गढ़ ही माना जाता रहा है।

जब पहला ही चुनाव हार गयी थीं डिंपल

2019 के आम चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन बाद ही मायावती ने सपा-बसपा गएबंधन तोड़ दिया था। असली वजह जो भी रही हो, लेकिन अखिलेश यादव के लिए कन्नौज में भी डिंपल यादव की हार ठीक दस साल पहले हुए फिरोजाबाद जैसा ही अनुभव रहा। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर यही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव खुद नामांकन नहीं दाखिल करने जा रहे ये 2009 की बात है। तब अखिलेश यादव फिरोजाबाद और कन्नौज दो लोक सभा सीटों से चुनाव लड़े थे। दोनों सीटों से जीते भी, लेकिन बाद में फिरोजाबाद छोड़ दी थी। जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो परिवार में डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने पर सहमति बनी। ये डिंपल यादव का पहला चुनाव था। लेकिन तभी राज बब्बर भी कांग्रेस से टिकट लेकर मैदान में कूद पड़े। मुलायम परिवार में किसी ने भी राज बब्बर की परवाह नहीं की। असल में राज बब्बर पहले समाजवादी पार्टी के ही नेता हुआ करते थे, लेकिन पार्टी में उनको लाने वाले अमर सिंह से तकरार बढ़ जाने पर निकाल दिया गया था। राज बब्बर के बाद ही अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को मुलायम सिंह यादव के परिवार और पार्टी से जोड़ा था, लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव से राज बब्बर को घुटन होने लगी थी और फिर नौबत ये आ गयी कि पार्टी से ही बेदखल होना पड़ा। फिरोजाबाद उपचुनाव राज बब्बर के लिए बदला लेने का बड़ा मौका समझ में आया।

चुनाव प्रचार के लिए जब राज बब्बर ने सलमान खान को बुला लिया तो, अमर सिंह ने संजय दत्त को बुला लिया डिंपल यादव के लिए वोट मांगने। अमर सिंह ने भी संजय दत्त के साथ रैली की, लेकिन सलमान खान को वॉन्टेड बोलकर सारे किये कराये पर खुद ही पानी फेर दिया। नतीजा आया तो डिंपल यादव चुनाव हार चुकी थीं और राज बब्बर जीत कर हिसाब बराबर कर चुके थे। पूरे परिवार में मायूसी छा गयी और उबरने में तीन साल लग गये लेकिन ये भी है कि डिंपल की वो हार समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई।

अखिलेश यादव के लिए डिंपल यादव की हार बहुत बड़ा सदमा रही। तब समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता से बाहर हो चुकी थी और मायावती अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिये बीएसपी की सरकार बनवा चुकी थीं। अखिलेश यादव ने सलाह मशविरा किया और साइकिल लेकर निकल पड़े। उसके बाद तो अगले विधानसभा चुनाव की तारीख आने तक अखिलेश यादव साइकिल पर ही सवार रहे और गांव गांव घूम कर लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते रहे। और तब तक मैदान में डटे रहे जब तक लोगों ने समाजवादी पार्टी को सत्ता नहीं सौंप दी। चुनाव में जीत के बाद आजम खान और शिवपाल यादव से लेकर तमाम सीनियर समाजवादी पार्टी नेता चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव ही मुख्यमंत्री बनें, लेकिन वो साफ तौर पर बोल दिये के ये अखिलेश की मेहनत का नतीजा है और कुर्सी के भी वही हकदार हैं। ये तो मुलायम सिंह का दबदबा ही रहा जो सारी चीजें मैनेज कर दिये और 2012 में डिंपल यादव को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया और वो संसद पहुंच गयीं। खास बात ये है कि तब भी डिंपल यादव को उपचुनाव में ही उतारा गया था और वो भी अखिलेश यादव की ही खाली की हुई सीट से। असल में 2012 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की

सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव पीछे हट गये और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने गये और उसी के चलते उनकी कन्नौज सीट खाली हो गयी थी। अव्वल को मुलायम परिवार को छाछ फूंककर पीने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सच तो यही रहा कि फिरोजबाद चुनाव का नतीजा दूध से जलने जैसा ही रहा। फिर क्या था। मुलायम सिंह यादव ने पूरी ताकत झोंक दी। फिर भी एक आदमी चुनाव मैदान में टपक पड़ा था। बहरहाल जैसे तैसे वो भी मैनेज हो गया और डिंपल यादव निर्विरोध चुनाव जीत कर संसद पहुंच गयीं।

डिंपल के मैदान में उतरने का मतलब

फिरोजाबाद की ही तरह पिछले आम चुनाव में हार का मुंह देख चुकीं डिंपल यादव के लिए मैनपुरी का मैदान कोई नया नहीं है, लेकिन कन्नौज की तरह तो वो मैनेज होने से रहा। बल्कि, ये लड़ाई तो और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मुलायम सिंह ने तो 2019 में ही मैनपुरी के लोगों से बोल दिया था कि वो अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि, वो अपना कार्यकाल भी नहीं पूरा कर पाये और अब उनके विरासत को बचाने और बनाये रखने की जिम्मेदारी बेटे अखिलेश यादव पर आ चुकी है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपने बाद समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा मैदान में उतार दिया है। हो सकता है अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के आखिरी चुनाव लड़ने की बात सोच कर ही मैनपुरी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीट करहल से चुनाव लड़ने का फैसला किया हो। ये तो है ही कि आजमगढ़ के मुकाबले अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी का किला बचाना कहीं ज्यादा जरूरी है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में पांच विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अखिलेश यादव की करहल सहित तीन विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि दो सीटों पर बीजेपी काबिज है। इस लिहाज से देखा जाये तो इलाके में आधे से ज्यादा दखल तो समाजवादी पार्टी का ही है, लेकिन चुनाव भी तो सर्जरी की ही तरह होता है जिसमें हमेशा ही जोखिम बना रहता है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का 1996 से ही कब्जा रहा है, जब मुलायम सिंह यादव खुद वहां से सांसद बने थे। अब तक मैनपुरी लोकसभा सीट पर दो बार उपचुनाव भी हो चुके हैं और ये तब से तीसरा उपचुनाव है। 2004 में हुआ उपचुनाव जीत कर धर्मेंद्र यादव संसद पहुंचे थे, लेकिन 2022 के आजमगढ़ उपचुनाव में वो बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ से मात खा गये। 2014 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़ दो सीटों से चुनाव लड़े और जीतने के बाद मैनपुरी सीट छोड़ दी थी। तब मुलायम परिवार के ही तेज प्रताप यादव सांसद बने और अब उनकी बहू डिंपल यादव मैदान में उतर चुकी हैं। हाल फिलहाल हो रहे उपचुनाव एक हिसाब से 2024 के आम चुनाव के लिए फीडबैक माने जा रहे हैं, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव का नतीजा तो अखिलेश यादव और यूपी में समाजवादी पार्टी के भविष्य की राह दिखाने वाला लगता है।

सौरभ गांगुली पर सब पार्टियों की नज़र

टीएमसी गांगुली पर दबाव तो नहीं बना रही है?

अमित राय

जब देश भर में छोटे छोटे खेल संगठनों में राजनीति हावी हो, फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जैसे खूब पैसे वाले संगठन का तो हक बनता है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के चुनाव का विवाद जब हाईकोर्ट पहुंचा तो रोक लगा दी गयी। दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए अध्यक्ष का दोबारा चुनाव लड़ रहे थे और जिला क्रिकेट संघों ने चुनाव अधिकारी की भूमिका पर ही सवाल उठा दिये थे। कोर्ट में दलील दी गयी कि जिस रिटायर्ड आईएएस अफसर को चुनाव अधिकारी बनाया गया है, जो सरकार की तरफ से लाभ का पद है और जब मुख्यमंत्री के बेटे ही दोबारा चुनाव लड़ रहे हों तो निष्पक्ष चुनाव की संभावना कितनी रह जाती है। सौरव गांगुली को लेकर तृणमूल कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी पर हमले से पहले हैरानी इसलिए भी हुई है, क्योंकि अभी महीना भर भी नहीं हुआ जब सौरव गांगुली के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत राहत भरा समझा जा रहा था। अपने संविधान संशोधन को लकेर बीसीसीआई की तरफ से ही दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अध्यक्ष सौरव गांगुली ही नहीं बल्कि सचिव जय शाह भी अगले तीन साल तक अपने पद पर रह सकते हैं। बीसीसीआई से अपनी याचिका के जरिये सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी व्यवस्था को रद्द किया जाये और ऐसी व्यवस्था हो कि संविधान में संशोधन के लिए अदालत में न जाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बीसीसीआई के एक बार के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं है, लेकिन दो कार्यकाल के बाद ऐसा जरूर करना होगा। तब ये माना जाने लगा था कि सौरव गांगुली और जय

शाह दोनों ही 2025 तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। खबर है कि जय शाह तो अपने दूसरे कार्यकाल में बने रहेंगे लेकिन सौरव गांगुली के साथ ऐसा नहीं होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ अध्यक्ष और सचिव ही नहीं बल्कि बीसीसीआई और राज्य एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों पर भी लागू होता है। कूलिंग ऑफ पीरियण का नियम 2018 में बनाया गया था। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी सवाल उठाने का मौका इसीलिए मिला है क्योंकि दूसरे कार्यकाल को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। एक वजह ये भी है कि जय शाह को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। टीएमसी के बीजेपी पर हमलावर होने की बड़ी वजह जय शाह का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा होना भी है।

तृणमूल कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सौरव गांगुली के बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार के चलते ही उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है। सच तो ये है कि 2011 में सत्ता परिवर्तन के बाद ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही सौरव गांगुली पर राजनीतिक दलों की तरफ से डोरे डाले जाते रहे हैं और सिर्फ बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस की ही कौन कहे, लेफ्ट की तरफ से भी कोशिशें कम नहीं हुई हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान सौरव गांगुली को लेकर कभी ऐसा लगता रहा कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो कभी तृणमूल कांग्रेस। कई वाकये तो ऐसे हुई भी जब अफवाहें भी सच के काफी करीब नजर आ रही थीं, लेकिन सौरव गांगुली की गुगली गुमराह करती हुई बार बार निकल जाती रही। न वो किसी को फायदा होने देते, न नुकसान ही। सौरव गांगुली न चाहते हुए भी लगता है, न माया मिली न राम वाली राजनीति के शिकार हुए लगते हैं। अगर ये सब, जैसे कि नये कयास शुरू हो चुके हैं, सौरव गांगुली के आईसीसी के चुनाव मैदान में उतरने को लेकर नहीं हो रहा है, फिर तो ऐसा ही समझा जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस का आरोप बगैर धुआं की

2011 में सत्ता परिवर्तन के बाद ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही सौरव गांगुली पर राजनीतिक दलों की तरफ से डोरे डाले जाते रहे हैं और सिर्फ बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस की ही कौन कहे, लेफ्ट की तरफ से भी कोशिशें कम नहीं हुई

आग नहीं है। सूत्रों के हवाले से ऐसी भी तो खबरें मीडिया में आयी ही हैं कि सौरव गांगुली बड़े गुस्से में दफ्तर से बाहर निकले थे। और ये भी कि सौरव गांगुली को लेकर बीसीसीआई के एक धड़ा काफी दिनों से खिलाफ लामबंद भी हो गया था। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि तृणमूल कांग्रेस का मकसद सौरव गांगुली के बहाने बीजेपी को कठघरे में खड़ा करना भर ही है या इरादा कुछ और ही है?

क्या गांगुली के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है?

पश्चिम बंगाल चुनावों के करीब डेढ़ साल बाद बीसीसीआई अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल से आने पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुल एक बार फिर राजनीति के केंद्रबिंद बन गये हैं। हां, इस बार भी सौरव गांगुली को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ही आमने सामने हैं।

सौरव गांगुली तृणमूल कांग्रेस के झांसे में आ सकते हैं क्या? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का सीधा सा सवाल है। अगर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह दूसरी पारी के लिए बीसीसीआई सचिव बने रह सकते हैं, तो सौरव गांगुली अगले कार्यकाल के लिए अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते? सौरव गांगुली के अलावा सिर्फ बीसीसीसीआई के संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज ही ऐसे हैं जिनको दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की आपत्ति की वजह भले ही जय शाह हों, लेकिन राजीव शुक्ला भी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनको चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है। पूरे घटनाक्रम को लेकर मीडिया रिपोर्ट में सौरव गांगुली को खफा भी बताया गया है। और कहा जा रहा है कि सौरव गांगुली ने अपनी नाराजगी छुपाने की कोई कोशिश भी नहीं की। दलील ये है कि परंपरा के मुताबिक मौजूदा अध्यक्ष बोर्ड के फैसले के बाद नये अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखना है, लेकिन सौरव गांगुली ऐसा कुछ किये बगैर ही चले गये। तृणमूल कांग्रेस का इल्जाम है कि ये सौरव गांगुली के अपमान की कोशिश है, और उसके पीछे बीजेपी है। टीएमसी नेताओं का दावा है कि सौरव गांगुली के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से टीएमसी नेताओं के आरोपों को सिरे से

> **तृणमूल कांग्रेस का इल्जाम है कि ये सौरव गांगुली के अपमान की कोशिश है, और उसके पीछे बीजेपी है। टीएमसी नेताओं का दावा है कि सौरव गांगुली के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए।**

खारिज किया गया है। बीजेपी का कहना है कि सौरव गांगुली को कभी पार्टी में शामिल करने की कोशिश ही नहीं की गयी। ऊपर से, बीजेपी ये सवाल भी पूछ रही है कि क्या तृणमूल कांग्रेस ने ही सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनवाया था? बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में क्रिकेट और क्रिकेटरों के हाल को लेकर भी सत्ताधारी टीएमसी को घेरने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे दिलीप घोष कहते हैं, जिन लोगों ने कभी सौरव गांगुली के लिए आवाज तक नहीं उठाई, वे आज उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। कार्यकाल पूरा हो गया। ऐसी राजनीति की क्या जरूरत है? बीजेपी के पलटवार पर टीएमसी प्रवक्ता ने साथी नेताओं का बचाव किया है। कह रहे हैं, हम इस मामले में सीधे तौर पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। चूंकि बीजेपी ने चुनाव के टाइम और बाद में भी ये सब प्रचारित किया था इसलिए सवाल उठाया गया है। कुणाल घोष का कहना है कि अब ये बीजेपी की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो समझाये कि सौरव गांगुली को अगली पारनी न देने के पीछे की वजह भी बताये। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने अमित शाह के सौरव गांगुली के घर डिनर का हवाला देते हुए सवाल उठाया है। शांतनु सेन कहते हैं, अमित शाह डिनर पर सौरव गांगुली के घर आए थे। वो चाहते थे कि सौरव गांगुली बीजेपी से जुड़ें। पहले भी बीजेपी की तरफ से सौरव गांगुली से ऐसा कहा गया था। वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए और ममता बनर्जी के राज्य से हैं, शायद इसीलिए उनको कीमत चुकानी पड़ी है।

मई, 2022 की ही बात है, पश्चिम बंगाल दौरे में अमित शाह और कुछ सीनियर बीजेपी नेता डिनर के लिए पहुंचे थे। अमित शाह के साथ बीजेपी सांसद स्वप्न दासगुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे थे। तभी ये जानना भी दिलचस्प रहा जब अमित शाह के साथ डिनर के अगले ही दिन सौरव गांगुली ने ममता बनर्जी को लेकर टिप्पणी की। सौरव गांगुली ने अमित शाह के साथ तो पुराना रिश्ता बताया ही, ममता बनर्जी के साथ बेहद करीबी संबंध की बात कही। और ममता बनर्जी ही नहीं, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम की भी खूब तारीफ की थी। ऐसा लगता है, तृणमूल कांग्रेस ने सौरव गांगुली के बाहने बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। टीएमसी नेता के टवीट से तो ऐसा ही लगता है। तृणमूल कांग्रेस के राज्य सभा सासंद शांतनु सेन टिवटर पर लिखते हैं, ये राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सचिव बने रह सकते हैं। सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हुए और वो पश्चिम बंगाल से हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है।

भोपाल गैस त्रासदी

पीड़ितों हेतु कार्यरत संगठनों ने ब्रिटेन संसद में ईडीएम की सराहना की

राजेन्द्र कानूनगो

भोपाल के निवासी 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को जो कि सन 1984 की थी, उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। उस समय भोपाल में स्थित एक रसायनिक फैक्ट्री, जिसे यूनियन कार्बाईड फैक्ट्री कहा जाता था, वहां से एक गैस MIC लीक हुई और उस गैस से भारी संख्या में लोगों की मौतें हुई और भारी संख्या में लोग पीड़ित भी हुए। उनकी पीड़ा का वर्णन करना बड़ा कठिन है। अनेक जानवरों की मौत भी हुई। जो लोग बच गए, वह और उनकी आगामी पीढ़ी उस खतरनाक गैस का परिणाम अभी भी भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस दुर्घटना में बच गए हैं उनके लिए कोई सहायता नहीं मिली। अनेक प्रकार की सहायता उन्हें प्रदान की गई जिसमें आर्थिक सहायता, खाद्यान की सहायता, इलाज की सहायता मिली और उसके पश्चात गैस की पीड़ा सहन करने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए गोविंदपुरा भोपाल में आईटीआई की भी स्थापना की गई, जहां ऐसे बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन फिर भी यह कोई न्याय नहीं कहा जा सकता। आदमी के जीवन की कोई लागत नहीं लगाई जा सकती। व्यक्ति को किसी प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा पहुंचा कर, उसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार की सहायता दे दी जाए यह कोई न्याय नहीं होता। यह एक अकाट्य

सत्य है, जिसे स्वीकार करना अति आवश्यक है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के हित में काम कर रहे पांच गैर सरकारी संगठनों ने बृहस्पतिवार को ब्रिटेन की संसद के उन सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने 28 नवंबर को संसद में पेश अर्ली डे मोशन (ईडीएम) पर हस्ताक्षर किए हैं। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए काम करने वाले इन पांच गैर सरकारी संगठनों ने जारी एक बयान में कहा कि ब्रिटेन के पांच राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और तीन स्वतंत्र सांसदों सहित संसद के 40 सदस्यों ने एक ईडीएम पर हस्ताक्षर किए हैं, जो गैस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय दिलाने के लिए कहता है, यूनियन कार्बाइड के मालिक डाव केमिकल से तत्काल सुधार करने के लिए कहता है। दो और तीन दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली जहरीली गैस के कारण कई हजार लोग मारे गए और लाखों लोग बीमार हो गए थे। इसे आमतौर पर दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा माना गया है। यह कारखाना अब निष्क्रिय है। यह महत्वपूर्ण है कि विपक्ष का नेतृत्व करने वाले जेरेमी कॉर्बिन और लेबर पार्टी के एंडी मैकडोनाल्ड ने ईडीएम का समर्थन किया है। इससे पहले नवेन्दु ने न्याय के मुद्दों, प्रदूषित भूमि और भूजल की सफाई और पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजे पर ब्रिटेन की संसद में बहस की। भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा, हमें उम्मीद है कि ब्रिटेन के सांसदों का सक्रिय समर्थन दुनिया भर के सांसदों को भोपाल के गैस पीड़ितों की मदद के लिए प्रेरित करेगा जो वर्तमान में पर्याप्त मुआवजे, मिट्टी और भूजल से जहर की सफाई, दोषी कंपनियों को सजा और चिकित्सा और सामाजिक पुनर्वास के लिए लड़ रहे हैं। विश्व की इस भयानक त्रासदी में, भारत के खासकर मध्यप्रदेश के भोपाल के निवासियों ने जो पीड़ा झेली है, उसका कोई अंदाजा लोग लगा नहीं सकते। हर सरकार और सरकार के नुमाइंदे 2 और 3 दिसंबर को मात्र श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला और भाषण देने वाला एक मौका मानते हैं, और उसे एक औपचारिकता की तरह निभाते हैं। लेकिन ना गैस पीड़ित विधवाओं और ना ही गैस पीड़ित नौजवानों के रोजगार के लिए कोई समुचित कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। आशा की जाती है कि मध्य प्रदेश के भोपाल के इन युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार अवश्य करेगी।

क्या भारत में एक देश एक आरक्षण व्यवस्था जरूरी है?

अर्चना शर्मा

सुप्रीम कोर्ट के माननीय पांच जजों में तीन ने इसे संविधान के मूल ढांचों से छेड़छाड़ करने की बातों को नकार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के कथन को कोट करते हुए कहा है कि हर दस साल में आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 10 प्रतिशत गरीब स्वर्णो को आर्थिक आधार पर आरक्षण के मामले में पांच बेंचों वाली कमेटी के फैसले ने एक बार फिर इसे बहस का मुद्दा बना दिया है। माननीय पांच जजों में तीन ने इसे संविधान के मूल ढांचों से छेड़छाड़ करने की बातों को नकार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के कथन को कोट करते हुए कहा है कि हर दस साल में आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि समाज में एकरूपता कायम हो सके। वहीं दो जजों का मानना था कि गरीब स्वर्णो के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। साल 2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण की मांगों को देखते हुए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर की गई थी। 8 लाख से कम आय तथा एक निश्चित मात्रा में जमीन का स्वामित्व रखने वाले परिवार के लोग इस आरक्षण के लिए पात्र हैं। लेकिन इस आरक्षण की वैधानिकता को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई थीं। देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी रोजगार, सरकारी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थाओं में नौकरी तथा सीटों में 49.5 फीसदी आरक्षण प्राप्त है।

अब सवाल यह है कि क्या देश में अभी भी आरक्षण की जरूरत है? जब भारत तरक्की की राह पर है तो उसे पीछे धकेलने की कोशिश क्यों की जा रही है। यदि आरक्षण की जरूरत है भी तो जब एक देश एक टैक्स, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक आधार कार्ड की व्यवस्था हो चुकी है और एक देश एक चुनाव की बात हो रही, तो ऐसे में एक देश एक आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? जो कि आर्थिक आधार पर हो जो इसमें किसी जाति, मजहब, लिंग, समुदाय आदि के साथ भेदभाव से मुक्त होने की व्यवस्था हो, क्योंकि गरीबी किसी भी समुदाय, जाति और लिंग से हो सकता है।

एक तरफ कहा जाता है कि जातिगत आरक्षण से समाज में एकरूपता ला रहें हैं। वहीं दूसरी तरफ इस आरक्षण के जरिए जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जातिगत आरक्षण या आर्थिक आधार पर आरक्षण, किसी भी प्रकार के आरक्षण की बात करते हुए यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि क्या आरक्षण अपने उद्देश्यों में कितना सफल हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आरक्षण अस्थायी व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया था, उसे राजनीतिक हथकंडा तो नहीं बन चुका है? इसका उत्तर आरक्षण की समीक्षा में निहित है। इससे अब तक परहेज किया जाता रहा है। दरअसल आरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में समानता को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही निम्न और पिछड़े वर्गो को हर क्षेत्र में समान अवसर मिलने की व्यवस्था करना था। जो आजादी के तत्कालीन सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थितियों के अनुसार ठीक था। परंतु बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि आरक्षण के जरिए किसी निश्चित अवधि में समाज की वंचित जातियां समाज के सशक्त

वर्गो के समकक्ष आ जाएगी। फिर आरक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज कुछ नेताओं, दलितों और पिछड़ों वर्गो को आरक्षण की ऐसी लत लग गई है कि वो छोड़ना नहीं चाहते।

दलित वर्ग आरक्षण को हटाने की पहल करेगा, ऐसा कभी संभव नहीं लगता। क्योंकि जिनको वैसाखी की आदत पड़ गई हो, वो भला उसे हटाने की बात क्यों करेंगे। आरक्षित वर्ग से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर यह वर्ग पीछे कैसे? आज दलित वर्ग का विकास काफी हो गया है। आज आरक्षण जारी रखने के विरोध में कुछ कहा जाए तो भावनात्मक दलीलें दी जाती हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ हजारों सालों के भेदभाव को कुछ दशकों में पूरा नहीं किया जा सकता है।

देश में 1960 अनुच्छेद 15(4) के तहत आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई थी तो बाबा साहब ने कहा था कि यह आरक्षण केवल दस वर्षो के लिए होना चाहिए। हर दस साल में इस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा होनी जरूरी है। वो चाहते थे कि सही व्यक्ति को इसका सही लाभ मिले। आरक्षण से किसी वर्ग का विकास होता है तो इसके आगे की पीढ़ी को इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही लोगों के लिए 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिलेयर शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि क्रिमिलेयर यानी संवैधानिक पदों पर आसीन पिछड़े तबके के व्यक्ति के परिवार एवं बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज भी राजनीतिक महकमा सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिलेयर का परिभाषा को मानने से इंकार करता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सवाल न उठाए इसके लिए आय में भारी मात्रा में इजाफा कर इसकी परिभाषा ही बदल दी गई। देश में आरक्षण के नाम पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, वो बेहद ही चिंताजनक है, जिस पर विचार होना चाहिए।

पराली से प्रदूषण
समस्या है तो समाधान भी है

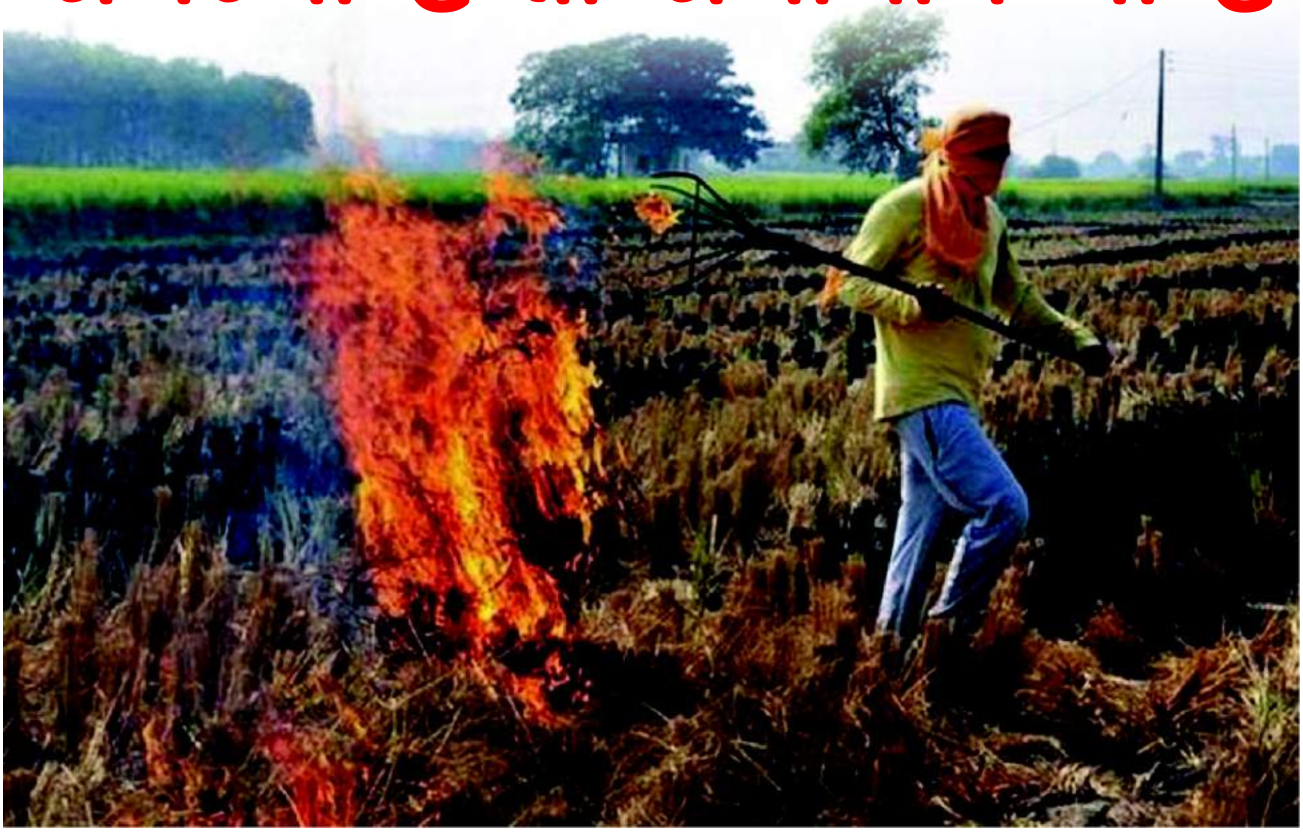

प्रशांत सिन्हा

हर वर्ष अक्टूबर महीना या यूं कहा जाए हल्की ठंड आते ही प्रदूषण जीवन में जहर घोलने लगता है। वातावरण में नमी से स्मॉग की स्थिति तक कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पराली जलने के मामलों में कमी नहीं आना भी है। पराली जलने के कारण उसका धुआं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहुंच रहा है।। जिससे हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) का बढ़ना शुरू हो गया है। जब भी ए क्यू आई 150 से ऊपर पहुंचता है यह इंसान को नुक़्सान पहुंचाने लगता है। दिल्ली और आसपास के शहरों का एक्यू आई 300-400 के आसपास इन दिनों रहता है।

वायु की खराब गुणवत्ता का रिश्ता दिल की बीमारी, फेफड़े के कैंसर, दमा और सांस के रोगों से है। वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों में मधुमेह की बिमारी बढ़ती जा रही है। बच्चों में तो जन्म से पहले गर्भ में ही वायु प्रदूषण जनित मुश्किलें शुरू हो जाती है। इस प्रदूषण के कारण साइबेरिया से आने वाले या अन्य प्रवासी पक्षियों में कमी आयी है। अगर यही हाल रहा तो परिंदों की तरह इंसान भी यहां से पलायन शुरू कर देंगे। साफ है कि प्रदूषण के मामले में केवल चिंता जताने का समय निकल गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबो हवा में सुधार अगर नहीं होता है तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो इससे निपटने के लिए केवल योजना बना सकते हैं लेकिन उस पर अमल करना राज्य सरकारों का काम है। सच्चाई यह है कि राजनेता निहित स्वार्थ के चलते सख्त कदम उठाने से कतराते हैं। कुछ साल से केंद्र सरकार से लेकर सर्वोच्च न्यायलय तक को पराली पर संज्ञान लेना पड़ा है। पिछले कुछ वर्षो में सर्वोच्च न्यायलय की डांट फटकार और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद जो कदम उठाए गए हैं उससे स्थिति में थोड़ा बहुत तो सुधार आया है लेकिन उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। मर्ज गहरा है, इलाज भी गंभीरता से करना होगा। सभी सरकारी विभागों को समन्वय के साथ मिल जुलकर काम करना होगा। व यह हमारा काम नहीं है क्यह कहकर पल्ला झाड़ लेने से बात नहीं बनेगी। राज्य और केंद्र सरकार को निगरानी व जवाबदेही दोनों तय करनी होगी। आमजन से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक की संकट बढ़ने पर तो ज़रूर सांसे फूलती है। प्रदूषण विशेषज्ञ चिंतन करते हैं फिर भी अच्छे परिणाम नहीं आते हैं।

कुछ वर्ष पहले पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव में पराली से चलने वाला पॉवर प्लांट भी पराली की समस्या से निजात नहीं दिला पाया। इसका कारण यह है कि पराली बेचने से किसानों को कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा है। एक एकड़ खेती में 15/20 क्विंटल पराली इकट्ठे हो जाती है। जबकि इसके गट्ठे बनाने पर लगभग पंद्रह सौ रुपए का खर्च आता है। पावर प्लांट तक ले जाने में परिवहन का खर्च अलग से। करीब तीन हजार रुपए ही मिल पाते हैं। फिर पराली उठाने की व्यवस्था सरकार के तरफ से नहीं है। किसानों को पराली बेचने की प्रक्रिया में काफी वक़्त लगता है। अगली फसल के लिए खेत भी तैयार करने होते हैं। इसलिए किसान पराली को बेचने के बजाय जला देते हैं। हालांकि बहुत सारे उपाय है जिससे पराली को जलाने से बचाया जा सके लेकिन उसके लिए ज़रूरत होती है इच्छाशक्ति। मशरूम पैदा करने के लिए पराली से शेड बनाई जा सकती है। पराली से तैयार ट्रे पर मशरूम उगाई जा सकती है। डेयरी में पशुओं को पराली का चारा के रूप इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कम्पोस्ट तैयार कर खेतों को उपयोगी उर्वरक दिया जा सकता है। अगर प्रदूषण को हमेशा के लिए खत्म करना है तो दीर्घकालिक उपायों को गति देने होंगे। निगरानी भी बढ़ानी होगी। समस्या का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कॉप 14 कार्यक्रम के सुझाव भी दिया था कि जिस तरह अफ्रीका में धूल को रोकने के लिए ग्रेट वॉल बनाई गई। उसी तरह भारत में भी पर्यावरण अपातकाल से मुक्ति के लिए ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाई जाए जो पश्चिमी विक्षोभ के साथ आने वाले धूल भरी हवाओं के दवाब को रोकने के लिए अवरोधक का काम करेगी।

वरदान बने बढ़ती आबादी

प्रमोद भार्गव

15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर गई। भारत के संदर्भ में देखें तो हैरानी में डालने वाली बात यह होगी कि 2023 में हम आबादी की दृष्टि से चीन से आगे निकल जाएंगे। बढ़ती जनसंख्या के जो आकड़े हैं, वे भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश को जहां एक बड़ी चुनौती हैं, वहीं उन्हें वरदान बनाने की जरूरत है। हालांकि जागरूकता और परिवार नियोजन के उपायों के चलते दुनिया में जन्मदर घटी है। जनसांख्यिकीय विश्लेषण के निष्कर्ष बताता है कि 1950 के बाद वर्तमान में जन्मदर सबसे कम है। अतएव यहां सवाल उठता है कि फिर आबादी का घनत्व क्यों बढ़ रहा है ? दरअसल चिकित्सा सुविधाओं और एक वर्ग विशेष की माली हैसियत बढ़ने से औसत उम्र बढ़ रही है। इस दायरे में आने वाले लोग उत्पादकता से जुड़े नहीं रहनें के बावजूद उच्च श्रेणी का जीवन जी रहे हैं। नतीजतन यह आबादी जापान, चीन और दक्षिण कोरिया की तरह भारत के युवाओं को रोजगार में बाधा बन रही है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी 15 से 36 आयु वर्ग के युवाओं में है। यदि हम पीपुल्स कमीशन की रिपोर्ट का उल्लेख करें तो 15 से 29 आयु समूह में बेरोजगारों की संख्या 27.8 करोड़ है। हालांकि इसमें अनेक बेरोजगार ऐसे हैं, जिनके पास काम तो है, लेकिन आमदनी का अनुपात संतोषजनक नहीं है। भारत के सीमांत राज्यों में विदेशियों की घुसपैइ और कमजोर जाति समूहों का धर्मांतरण भी आबादी का घनत्व बढ़ाने और बिगाड़ते हुए रोजगार के संकट के साथ स्थानीय मूल निवासियों से टकराव के हालात उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए जनसंख्या नीति में समानता की बात की जा रही है।

2023 में चीन से हमारी आबादी अधिक हो जाएगी, तब हमें चीन से यह सबक लेने की जरूरत है कि उसने अपने मानव संसाधन को किस तरह से श्रम और उत्पादकता से जोड़ा। क्योंकि चीन में बड़ी आबादी के बावजूद रोजगार का संकट भारत की तरह नहीं गहराया। जाहिर है, चीन की उन्नति और उत्पदकता में इसी आबादी का रचनात्मक योगदान रहा है। सस्ते कुशल एवं अर्द्धकुशल लोगों से उत्पादन कराकर चीन ने अपना माल दुनिया के बाजारों में भर दिया है। जबकि भारत बड़ी कंपनियों को सब्सिडी देने के

बावजूद स्वदेशी उत्पादन में आबादी के अनुपात में उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पाया है। मेक इल इंडिया के नाम पर हाल ही में दो कंपनियों हीरो इलेक्ट्रिक और ओकीनावा की 370 करोड़ रुपए की सब्सिडी की राशि देने पर सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने फास्टर एडॉप्सन एंड मैन्यू फैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम)-2 योजना के तहत दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु 10,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन को सब्सिडी दी जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 15000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। लेकिन यह सब्सिडी तभी दी जाएगी, जब उत्पादन स्वदेषी के स्तर पर किया जाए। लेकिन सरकार ने जब जांच की तो पाया कि इन कंपनियों ने इन वाहनों में चीन से आयात कल-पुर्जे इस्तेमाल किए हैं। इसी कारण दो पहिया वाहनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस धोखाधड़ी के चलते हीरो इलेक्ट्रिक की 220 करोड़ और ओकीनावा की 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी रोक दी। इन धोखाधड़ियों के चलते भी भारत स्वदेषीकरण के साथ बेरोजगारी से पार नहीं पा रहा है।

यदि हम चीन में ज्ञान-परंपरा से दीक्षित लोगों को रोजगार देने की बात करें तो वहां सरकार या कंपनी द्वारा गांव-गांव कच्चा माल पहुंचाया जाता है। जब वस्तु का निर्माण हो जाता है, तो उस माल को लाने और मौके पर ही भुगतान करने की जबावदेही संस्थागत है। इसका फायदा यह होता है कि ग्रामीण अपने घर में ही वस्तु का उत्पादन कर लेता है। नतीजतन वस्तु की लागत न्यूनतम होती है। यदि यही व्यक्ति शहर में जाकर उत्पदकता से जुड़े तो उसे कमाई की बड़ी राषि रहने, खाने-पीने और यातायात में खर्च करने पड़ जाती है। भारत में उत्पादन के छोटे-बड़े कारखाने षहरों में हैं। लिहाजा वस्तु की लागत अधिक आती है। चीन में होली, दिवाली और रक्षाबंधन से जुड़ी जो वस्तुएं निर्यात होती हैं, उनका उत्पादन गांव में ही होता है। जाहिर है, यदि बड़ी जनसंख्या उत्पादन से जुड़ जाए तो कोई समस्या नहीं रह जाती है। वह समस्या तब बनती है, जब उसके हाथों में काम न हो? जापान और दक्षिण कोरिया में जनसंख्या का घनत्व भारत से ज्यादा है, बावजूद ये देश हमसे अधिक संमृद्ध होने के साथ स्वदेषी प्रौद्योगिकी से उत्पादन और उसके निर्यात में हमसे आगे हैं। अतएव भारत को चीन, जापान और कोरिया से सीख लेने की जरूरत है।

यह बात लोगों को रोजगार से जोड़ने की हुई, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर एक नीति बने बिना बात बनने वाली नहीं है। दो बच्चों की यह नीति सभी धर्म एवं समुदायों के लोगों पर समान रूप से लागू हो। क्योंकि जनसंख्या एक समस्या भी है और एक साधन भी है। लेकिन जिस तरह से देष के सीमांत प्रांतों और कश्मीर में जनसंख्यात्मक घनत्व बिगड़ रहा है, उस संदर्भ में जरूरी हो जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द वजूद में आए। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ हिंदुओं की आबादी घटने पर कई बार चिंता जता चुका है। साथ ही हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह भी संघ के कार्यवाहक देते रहे हैं। इन बयानों को अब तक हिंदु पक्षधरता के दायरे में समेटने की संकीर्ण मानसिकता जताई जाती है, जबकि इसे व्यापक दायरे में लेने की जरूरत है। कश्मीर, केरल समेत अन्य सीमांत प्रदेशों में बिगड़ते जनसंख्यात्मक अनुपात के दुष्परिणाम कुछ समय से प्रत्यक्ष रूप में देखने में आ रहें हैं। कष्मीर में पुश्तैनी धरती से 5 लाख विस्थापित हिंदुओं का पुर्नवास धारा-370 हटने के बाद भी आतंकी घटनाओं के चलते नहीं हो पाया है। बांग्लादेशी धुसपैठियों के चलते असम व अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बदलते जनसंख्यात्मक घनत्व के कारण जब चाहे तब दंगों के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। यही हालात पश्चिम बंगाल में देखने में आ रहे हैं। जबरिया धर्मांतरण पूर्वोत्तर और केरल राज्यों में बढ़ता ईसाई वर्चस्व ऐसी बड़ी वजह बन रही हैं, जो देष के मौजूदा नक्षे की षक्ल बदल सकती हैं? लिहाजा परिवार नियोजन के एकांगी उपायों को खारिज करते हुए आबादी नियंत्रण के उपायों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। क्योंकि ये घुसपैठिए मूल निवासियों को परंपरागत संसाधनों से बेदखल कर बेरोजगारी बढ़ाने काम कर रहे है।

There is a fundamental error in the thinking of the Pandit Nehru

Pandit Deendayal Upadhyaya
[Organiser, 28 August, 1961]

The Merger of Nagar Haveli and Dadra into the Indian union is a move in the right direction. That the Government of India should have taken seven long years to make this simple decision only shows that mental state of indecisiveness of the rulers. What Sardar Patel could do within days in the case of Janagadh, Pandit Nehru has taken years to accomplish. Besides the inordinate delay, there is a basic difference towards the issue of liberating, and integrating, areas laying outside the pale of considered it the Government's duty to actively work for their freedom and merger and he was his armoury to achieve his objective. Pandit Nehru it seems is not prepared to shoulder this responsibility. Neither is he prepared to go to the lengths to which Sardar Patel went in the case of Hyderabad.

Apart from temper-amental weaknesses and hesitancy, there is a fundamental error in the thinking of the Prime Minister. He thinks within the frame-work of the Government of India Act of 1935 or the India Independence Act of 1946. The Sovereignty of India accordingly is limited to the territories handed over to her by the Britisher and/or to States that join the dominion. In all other cases the people of the different areas are to be the architects of their fate and their future. If they desire to be independent, they must struggle. The status that they would enjoy is also to be determined by them. This line of

thinking ignores the basic fact of India being one. It does not recognise the existence of an Indian nation, which by historical accident came under the dominion of a number of Western powers. If the tiny territory of Goa was, and is ruled by Portugal while the rest of the country was under the British rule and now independent, it did not and does not in any way create a separate Goanese people. The people of Goa are part and parcel of the Bharatiya Nation. The struggle for the liberation of these territories is therefore an integral part of our freedom struggle. Those who say that the people of Goa themselves should fight for their independence are propounding a theory which is dangerous and unnational.

The merger of Nagar Haveli and Dadra has been effected in accordance with the wishes of the people of these areas. It is good and natural that these people have chosen to become part of the political set-up of the country. But any insistence on

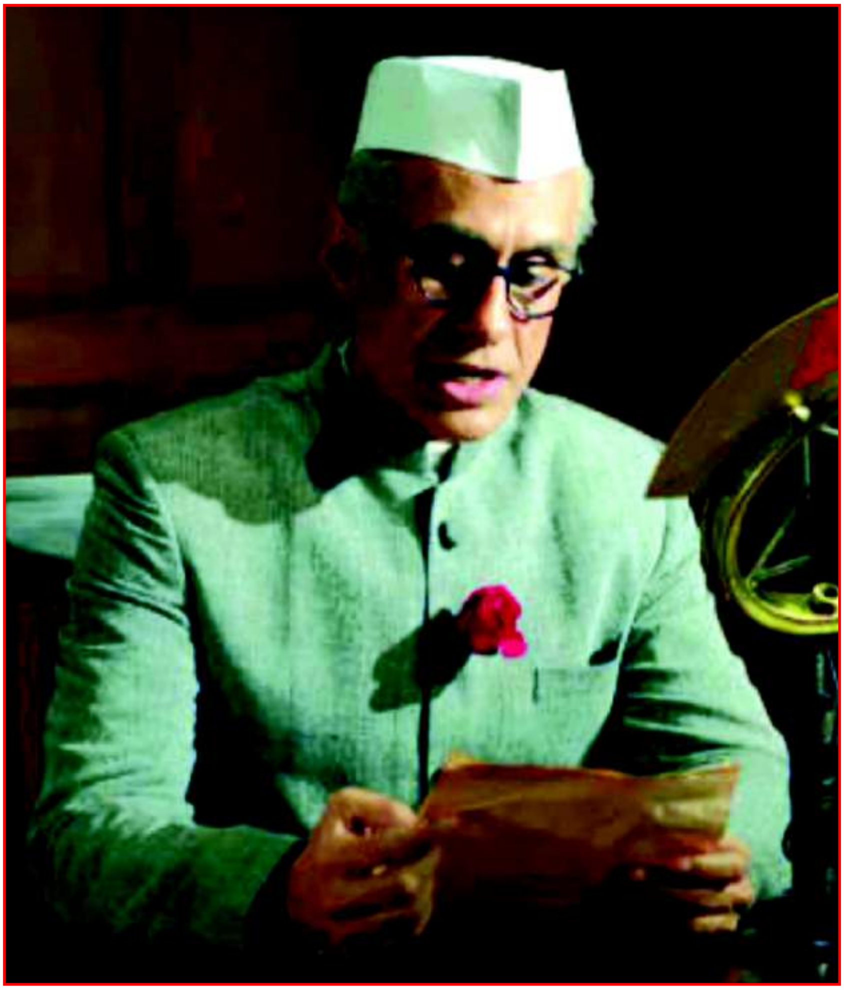

The Merger of Nagar Haveli and Dadra into the Indian union is a move in the right direction. That the Government of India should have taken seven long years to make this simple decision only shows that mental state of indecisiveness of the rulers. What Sardar Patel could do within days in the case of Janagadh, Pandit Nehru has taken years to accomplish.

the right of these people to determine their future deprives the people of India their fundamental sovereignty over the whole land. It is on this account that the French enclaves in spite of their de facto transfer to India have not yet become part of the India union. The Government is waiting for a legal flat by the French Government. Why should we look to the French for legalising the transfer? The territory is ours and if the French have given it peacefully, it can be credited to

Deendayal Upadhyaya : BJP's 'Gandhi' !

their good sense or common sense, but it cannot confer upon them any legal title to hold the areas even technically. Our Constitution gives us a right to acquire territories and we should act accordingly. Let the French take care of their Constitution. Let them amend or mend it, and at leisure. But we cannot delay the process of our national integration.

Nagar Haveli and Dadra, like the French enclaves, have been kept as a separate unit. They are to be administered under the External Affairs Ministry. It is wrong. The areas should be straightway merged with the adjoining districts. That alone will demonstrate our unity with these people.

With regard to Goa, the Bharatiya Jana Sangh had all along felt that the problem can be solved only by police action. It is a matter of satisfaction that the political opinion in the country has veered round to this view. Even the Prime Minister,

AKHAND BHARAT AND NATIONALISM

THE words 'Akhand Bharat' (un-divided India) include all those basic values of nationalism and an integral culture that the Jana Sangh has accepted. These words include the feeling that this entire land from Attock to Cutack, Kutch to Kamrup and Kashmir to Kanya Kumari is not only sacred to us but is a part of us. The people who have been born in it since times immemorial and who still live in it may have all the differences superficially brought about by place and time, but the basic unity of their entire life can be seen in every devotee of Akhand Bharat.

Shri Bala Saheb Deoras of R.S.S., Shri Atal Bihari Vajpayee, Rajmata Vijaya Raje Scindia and others on the occasion of the doundation laying ceremony of houses for Deendayal Dham service projects of Nagla Chandrahan on 13 July, 1982

who had all these years persistently refused to take resort to military force, has said that military action cannot be ruled out. It is a major change in the Government's policy and is in the correct direction. For the first time after Sardar Patel, Government spokesmen have asserted that the military can be used for the purpose which it is being maintained for. But there is a feeling in the people that all this talk is meant only to please the electorate.

The stiffness on the Goa issue is also meant to divert the attention of the people from the Government's failure on other fronts, notable the China and the Pakistan fronts. It is for this reason that the communists who had practically forgotten Goa have again become active and a new committee headed by Srimati Aruna Asaf Ali has been formed.

Whatever be the motive, liberation of Goa is desired by all. But when shall the Government do it? Will they take some active steps or simply fight a verbal battle? The people, who have been accustomed to such declarations, will not feel satisfied without any practical steps. Pandit Nehru will be wrong if he thinks that he can dupe the nation simply be verbal assurances. Let him fulfil his assurances not within his life-time but before the elections if he wants to reap its advantages for his party.

Even before steps for the liberation of these territories are taken, it would be desirable that the Goans living in the Indian union are granted Citizenship and franchise rights. It will establish our bona fide and demonstrate that we look upon these people as part and parcel of our nation.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.